लखनऊ

गुरुवार 22 जनवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 153

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

अर्जुन की तरह आप अपना चित्त केवल लक्ष्य पर केन्द्रित करें, एकाग्रता ही आपको सफलता दिलायेगी।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

संक्षेप

भारत में रीजनल यात्री विमान बनाने की तैयारी, सरकार खर्च करेगी 12,500 करोड़ रुपये

नईदिल्ली। केंद्र सरकार देश में एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विकसित करने के लिए एक खास कंपनी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) बनाने की योजना पर काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट पर करीब 12,511 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सबसे अहम बात यह है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा विमान के डिजाइन से ज्यादा उसके सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, जिससे सिविल विमान निर्माण की जटिलता साफ दिखती है। प्रस्तावित एसपीवी को एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया जाएगा, जो पूरे एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को डिजाइन से लेकर सर्टिफिकेशन और फिर प्रोडक्शन तक आगे बढ़ाएगा। इसका मकसद सरकारी सहयोग, तकनीकी भागीदारों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक साथ लाना है। केंद्र सरकार इस एसपीवी के जरिए फंडिंग, साझेदारी और कामकाज के बेहतर तालमेल को सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि जिम्मेदारियां अलग-अलग एजेंसियों में बंटने से बच सकें। इस प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका भी अहम होगी। डिजाइन, सर्टिफिकेशन और फ्लाइट टेस्टिंग के लिए एक विदेशी नॉलेज पार्टनर को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिस पर करीब 750 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विमान वैश्विक सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे।

दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आधुनिक कॉरिडोर को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। अगले महीने दिल्ली में बीजेपी सरकार अपने गठन के एक साल पूरा करने जा रही है। ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार अपने किए वादों को मद्देनजर सक्रिया नजर आ रही है। दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में वित्त व्यय समिति ने दक्षिण दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत, एमबी रोड पर साकेत जी-ब्लॉक से पुल प्रह्लादपुर तक 6-लेन का एकीकृत एलिवेटेड रोड और दो अंडरपास भी बनेंगे। इनके निर्माण से दक्षिण दिल्ली के लोगों को लंबे समय से जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। यह परियोजना न केवल यातायात के दबाव को कम करेगी, बल्कि आवागमन का समय भी घटाएगी। परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पर करीब 1471.14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बैठक में परियोजना की तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक रूपरेखा पर विस्तार से विचार-विमर्श के बाद इसे स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह परियोजना दक्षिण दिल्ली के यातायात नेटवर्क को अधिक सुव्यवस्थित और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम सिद्ध होगी। करीब पांच किलोमीटर लंबी यह परियोजना दो भागों में बनेगी। पहला एलिवेटेड रोड साकेत जी ब्लॉक से संगम विहार तक होगा। इसकी लंबाई 2.42 किलोमीटर होगी, दूसरा मां आनंदमई मार्ग से पुल प्रह्लादपुर तक बनेगा। इसकी लंबाई करीब 2.48 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) करेगा।

'शुद्ध मतदाता सूची ही लोकतंत्र की असली ताकत', एसआईआर पर विपक्ष के सवालों के बीच ज्ञानेश कुमार का जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी चर्चाओं के बीच चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ किया है। आयोग ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच बुधवार को कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही लोकतंत्र को मजबूत करने की कुंजी है। यह बात मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने अंतरराष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन संगोष्ठी (IICDEM-2026) के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने बताया कि बिहार में पिछले साल हुए मतदाता सूची संशोधन के दौरान किसी भी मतदाता की शामिल या हटाने की कार्रवाई को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई।

वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में किसी भी एक लाख मतदान केंद्रों पर एक भी री-पोलिंग (दोबारा मतदान) की जरूरत नहीं पड़ी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कानून के अनुसार हर मतदाता को शामिल करने वाली शुद्ध मतदाता सूची ही लोकतंत्र को मजबूत करती है और इसके आधार पर आयोजित सभी चुनाव निष्पक्ष होंगे।

एसआईआर का दूसरा चरण

बता दें कि विशेष मतदाता सूची संशोधन का दूसरा चरण 4 नवंबर, 2025 से अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। असम में अलग से 'विशेष संशोधन' जारी है। आयोग का कहना है कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य जन्म स्थान की जांच कर अवैध प्रवासियों को हटाना है, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों को।

विपक्ष के सवाल और ज्ञानेश कुमार का जवाब

ज्ञानेश कुमार ने आगे बताया कि बिहार में मतदाता सूची संशोधन और चुनाव संचालन में स्थानीय चुनाव मशीनरी ने बहुत दक्षता दिखाई। विपक्षी दल इस विशेष मतदाता सूची संशोधन पर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि यह वोटों में हेरफेर का एक प्रयास है, लेकिन सरकार और आयोग ने इसे खारिज कर दिया है।

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह ने क्या कहा?

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि नागरिकों का चुनाव प्रबंधन संस्थाओं पर रखा विश्वास अनमोल है। हर चुनाव के केंद्र में नागरिक होता है और यह सुनिश्चित करना चुनाव प्रबंधन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उनके चुनावी अधिकारों का सम्मान हो। दूसरी ओर आयोग के सदस्य विवेक जोशी ने कहा कि IICDEM-2026 सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय, शोधकर्ता और छात्र भाग ले रहे हैं, जो चुनावों के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर अपने-अपने संस्थानों में योगदान देंगे। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में लगभग 100 प्रतिनिधि करीब 70 देशों से शामिल हुए हैं, और यह भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है।

अमित शाह ने बताया क्यों गीता प्रेस बिना एडवर्टाइजमेंटके चलता है

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को गीता प्रेस और उसकी मासिक पत्रिका 'कल्याण' की 'सनातन धर्म' और भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों के सृजन के लिए काम करती है। शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, ऋषिकेश के गीता भवन में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'कल्याण' के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में उपस्थित थे। गीता भवन में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस सभा में उपस्थित गीता प्रेस और कल्याण के सभी पाठकों और प्रशंसकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल्याण पत्रिका के 100वें अंक के विमोचन के इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने का अवसर देने के लिए मैं गीता प्रेस का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

पीएम मोदी के 'अच्छे दोस्त' ट्रंप का नया दावा, जयराम रमेश बोले- 'जबरन गले लगने' का नतीजा!

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप ने 10 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए 70 बार दावा किया है। X पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि एक दिन पहले तक ट्रंप ने ऑपरेशन को रोकने में 68 बार अपनी संलिप्तता का दावा किया था, जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआती बयान और बाद में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान अचानक बढ़कर 70 हो गया। रमेश ने लिखा कि कल से पहले यह संख्या 68 थी। हालांकि, कल ही यह आंकड़ा 69 तक नहीं पहुंचा, बल्कि सीधे 70 हो गया, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआती बयान और बाद में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्रंप को गले लगाने के स्वागत भाव पर भी कटाक्ष किया। रमेश ने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री के 'अच्छे दोस्त', जिन्हें प्रधानमंत्री के जबरन गले लगाने का भी कई बार सामना करना पड़ा है, ने इतनी बार दावा किया है कि 10 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के अचानक और अप्रत्याशित रूप से रुकने के लिए वे अकेले ही जिम्मेदार थे।'

शिंदे गुट की मांग को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा : संजय राउत

मुंबई, एजेंसी। मुंबई महानगरपालिका के मेयर पद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके शिवसेना गुट पर फिर हमला बोला है। संजय राउत ने दावा किया कि बीएमसी मेयर पद को लेकर शिंदे गुट की मांग को न तो कोई गंभीरता से ले रहा है और न ही उन्हें कोई सुन रहा है।

संजय राउत ने कहा, "मेरे पास बहुत अंदर की जानकारी है। अंदर की खबर यह है कि शिंदे को कोई सुन नहीं रहा, ना ही उनकी मेयर पद की मांग को गंभीरता से लिया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि मुंबई के मेयर पद के लिए इतिहास में पहली बार

खुद को 'शिवसेना' कहने वाले और बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर लगाने वाले नेताओं को दिल्ली जाकर गुजराती नेताओं के चरणों में बैठना पड़ रहा है।

संजय राउत ने तीखे शब्दों में कहा, "इससे ज्यादा अपमानजनक बात मुझे दूसरी कोई नहीं दिखती। यह उनका हक है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन अमित शाह की पार्टी ने अगर कोई मांग की है तो वह पूरी होगी या नहीं, यह देखना पड़ेगा। शिंदे गुट को बार-बार हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, झोली फैलानी पड़ रही है और यह सब महाराष्ट्र देख रहा है।"

'बालासाहेब का नाम मत लीजिए'

बालासाहेब ठाकरे के नाम को लेकर भी संजय राउत ने शिंदे गुट पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "बालासाहेब का नाम मत लीजिए। बालासाहेब की शताब्दी से आपका कोई संबंध नहीं है, यह याद रखिए। आपने गद्दारी करके भाजपा का 'मैल' खाया है, तो उस मुंह से बालासाहेब का नाम मत लीजिए, बस इतना ही मैं कहूंगा।"

केरल में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या साथ में? उलझन को दूर करने के लिए राहुल-खरगे ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। बंगाल चुनाव में कांग्रेस का रुख क्या हो, ये मामला बंगाल में तो अभी तक उलझा ही हुआ था, लेकिन अब मसले में केरल कांग्रेस भी कूद पड़ी है। मसले की गंभीरता देख कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 23 जनवरी को दिल्ली में केरल कांग्रेस की बैठक बुलाई है।

बंगाल में इंडिया ब्लॉक के केंद्रीय स्तर पर तीन दल हैं- टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि उसे राज्य में अकेले जाना है या फिर लेफ्ट या टीएमसी से गठबंधन करना है। नए प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार अकेले जाने के पक्ष में राय दे चुके हैं, तो वहीं टीएमसी के धुर-विरोधी पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लेफ्ट के साथ तालमेल की वकालत कर चुके हैं। ऐसे में आलाकमान ने जमीनी हालात परखने के लिए सभी 33 जिलाध्यक्षों की राय ली। सूत्रों के मुताबिक, इसमें 30 ने अकेले जाने, 2 ने लेफ्ट के साथ तालमेल करने और 1 ने ममता के साथ गठजोड़ की वकालत की है। अभी आलाकमान इस पर मंथन पूरा कर भी नहीं पाया था कि केरल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखकर आलाकमान का सियासी सिरदर्द बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की केरल यूनिट का कहना है कि केरल में कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनने की प्रबल संभावना है, जबकि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई के बीच लेफ्ट-कांग्रेस का गठबंधन पिछली बार भी धड़ाम ही हुआ था। साथ ही इस बार भी लेफ्ट से गठजोड़ करके कुछ खास होता नहीं दिख रहा, लेकिन अगर बंगाल में पार्टी लेफ्ट से गठजोड़ करती है तो उसका केरल में नकारात्मक असर पड़ेगा। एक तो बीजेपी को अपनी जड़ें मजबूत करने का ये कहकर मौका मिलेगा कि केरल में आमने-सामने और बंगाल में एक साथ यानी लेफ्ट कांग्रेस की केरल में लड़ाई महज दिखावा है। इसके अलावा जनता के एक तबके में भी गलत संकेत जाएगा कि लेफ्ट के नेतृत्व की सरकार और विपक्षी कांग्रेस गठजोड़ की सियासी अदावत महज दिखावा है, ऐसे में किसी को वोट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होने वाला वोटर ढीला पड़ सकता है।

इंडिया ब्लॉक में चल रही उथल-पुथल से केंद्रीय नेतृत्व चिंतित

वहीं, केंद्रीय नेतृत्व की मुश्किल ये है कि इंडिया ब्लॉक में चल रही उथल-पुथल से वो पहले ही चिंतित है। ऐसे में दो बड़े राज्यों में उसके अकेले जाने पर इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ नजर आएगा। साथ ही बंगाल में तालमेल न करने पर केंद्र में उसका मजबूत साथी लेफ्ट भी नाराज हो सकता है।

सुखना झील को और कितना सुखाओगे... अधिकारियों और बिल्डर माफिया पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में आज अरावली मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ की सुखना झील के सूखने पर गंभीर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए प्रशासन से पूछा है कि और कितना सुखना झील को सुखाओगे? कोर्ट ने सुखना के सूखने को अवैध निम्राण से जोड़ा है।

SC ने चंडीगढ़ की ऐतिहासिक सुखना झील की दुर्दशा पर हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। CJI सूर्य कांत की बेंच ने बिल्डर माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से झील को हुए नुकसान पर चिंता जताई। कोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े टीएन गोदाबर्मन मामले में यह टिप्पणी करते हुए SC ने पिछली गलतियों को न दोहराने को कहा है। दोहराने की चेतावनी देते हुए कहा अधिकारियों और बिल्डर माफिया की मिलीभगत से सुखना झील पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

SC ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर माफिया एक्टिव हैं आप सुखना झील को कितना सूखा देंगे, आपने झील को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पर्यावरण से जुड़े टी एन गोदाबर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुखना झील को और कितना सुखाओगे? CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा सरकार को चेतावनी है। कोर्ट ने पिछली गलतियों को न

कोर्ट ने क्यों की तल्ख टिप्पणी

सुखना लेक चंडीगढ़ में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद है। इसके साथ ही यह एक मशहूर झील है, जिसे हर कोई जानता है। एक तरह से यह चंडीगढ़ की पहचान है।पिछले कुछ समय से उसकी हालत ठीक नहीं है। इसके आस-पास के इलाके पर कब्जा हो गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट की यह टिप्पणी न सिर्फ सरकार के लिए है बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी है।

नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में खुलासा, बिल्डर ने 3 साल पहले दी थी चेतावनी

आर्यावर्त क्रांति

नोएडा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में बड़ी व्यवस्थागत लापरवाही सामने आई है। जिस बिल्डर के निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर की मौत हुई है, उस बिल्डर कंपनी अर्थम (विजटाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड) का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में बिल्डर कंपनी ने 3 साल पहले नोएडा प्राधिकरण को साइट पर मौजूद खतरनाक स्थितियों के बारे में आगाह किया था।

बिल्डर फर्म विजटाउन प्लानर्स की निदेशक अंचल बोहरा ने 14 मार्च, 2022 को यह पत्र नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को लिखा था, जिसमें सीवर और मुख्य नाली लाइनों के ढहने की बात कहते हुए तुरंत हस्तक्षेप की मदद मांगी थी। पत्र में कंपनी ने चेतावनी दी, अगर सीवर और ड्रेन लाइन तुरंत ठीक नहीं किया गया और भूखंड से नाली का पानी बाहर नहीं निकाला गया, तो गंभीर दुर्घटना और अनजाने में हादसे हो सकते हैं।

बिल्डर ने पत्र में यह भी बताया कि काफी लंबे समय से जलभराव के कारण भूखंड की चारदीवारी कमजोर हो गई थी, जिससे उसके कुछ हिस्से ढह गए थे। कंपनी ने चेतावनी दी थी कि सड़कों के धंसने और जल दबाव के बढ़ने के कारण साइट पर लगाए गए अस्थायी अवरोध भी विफल हो रहे हैं।

'आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का रवैया अहम'; स्पेन के विदेश मंत्री के साथ बैठक में बोले जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भारत और स्पेन दोनों आतंकवाद के शिकार रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने बदलती दुनिया में साझा चुनौतियों से मिलकर लड़ने पर जोर दिया।

जयशंकर ने 18 जनवरी को स्पेन के कॉर्डोबा में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर गहरा दुख जताया। इस हादसे में 40 लोगों की जान गई थी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के

जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। यह हादसा तब हुआ था जब एक ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरी ट्रेन से टकरा गई थी। दुर्घटना में शामिल ट्रेनों में से एक में मलागा से मैड्रिड तक लगभग 300 लोग और दूसरी में मैड्रिड से हुएल्वा तक लगभग 200 लोग सवार थे।

रिश्तों के 70 साल और नया लोगो

साल 2026 भारत और स्पेन के रिश्तों के लिए बेहद खास है। दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दोहरा वर्ष भी मनाया जा रहा है। जयशंकर ने इस अवसर के लिए एक खास लोगो भी लॉन्च किया, जिसे एक प्रतियोगिता के जरिए चुना गया है।

रक्षा और एआई में बढ़ रहा सहयोग

रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बात करते हुए जयशंकर ने बताया कि 'मेड इन इंडिया' सी-295 विमान इस साल सितंबर से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। वडोदरा में इसकी फैक्ट्री का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में हुआ था। इसके अलावा, भारत अगले महीने एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। भारत एआई के सही और नैतिक इस्तेमाल के पक्ष में

एआई तैयारी पर आईएमएफ की रैंकिंग से असहमत भारत, अश्विनी वैष्णव ने उठाए सवाल

नईदिल्ली,21 जनवरी (आरएनएस)। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में देशों की तैयारी को लेकर रैंकिंग सूची जारी की है। इस सूची में भारत को दूसरे ग्रुप में रखा गया है, जिस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भारत एआई के लिए पूरी तरह तैयार है और उसे पहले ग्रुप में रखा जाना चाहिए, क्योंकि देश लगातार तकनीक, डिजिटल सेवाओं और इनोवेशन की क्षमता को मजबूत कर रहा है।

डब्ल्यूईएफ के मंच पर आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इंडेक्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस इंडेक्स से यह आंका जाता है कि कोई देश एआई के लिए कितना तैयार है। आईएमएफ इस

व्यापार और संस्कृति को मिल रहा बढ़ावा

व्यापार के मामले में स्पेन भारत का अहम साथी है। दोनों देशों के बीच 8 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। स्पेन की कंपनियां भारत में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रही हैं। वहीं, भारतीय कंपनियां भी स्पेन में सक्रिय हैं। जयशंकर ने यह भी कहा स्पेन में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता, और भारत में स्पेनिश भाषा और संस्कृति में बढ़ती दिलचस्पी हमारे समाजों के बीच गहरे लोगों से लोगों के जुड़ाव को

संभल में एक्शन: बवाल के मास्टरमाइंड पर कसा शिकंजा, शारिक साटा की संपत्ति की कुर्की, कोर्ट ने दिए थे आदेश

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता दीपा सराय निवासी शारिक साटा की संपत्ति कुर्क की जा रही है। भारी संख्या में पुलिसबल तैनात है। कुर्की का आदेश कोर्ट से होने के बाद कार्रवाई की गई है। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक के घर पर कोर्ट के आदेश पर उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं।

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, शारिक की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, यह प्रॉपर्टी शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक में है। इस बिल्डिंग में चार मंजिलें हैं, लेकिन सिर्फ फरार आरोपी की मिल्कियत वाली मंजिल को ही अटैच किया गया है।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शारिक के घर को अटैच कर लिया है। बवाल में मुख्य साजिशकर्ता आरोपी शारिक साटा के खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत तीन रिपोर्ट दर्ज की गई थीं। यह कार्रवाई न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते की जाती है। इसी क्रम में अब कोर्ट द्वारा कुर्की का आदेश किया गया है।

बवाल के दौरान चलाई थीं गोलियां

एसपी ने बताया कि शारिक साटा के खिलाफ मुख्य अपराध संख्या 340/24 और 306/24 में हत्या की साजिश करने, बवाल की साजिश रचने व अन्य गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। साटा के गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस ने बवाल के दौरान गोलियां चलाई थीं।

इसमें आम लोगों की मौत हो गई थी। अज्ञात में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस गिरोह की भूमिका मिलने पर तीनों गुर्गों को गिरफ्तार किया था। इसमें मुल्ला अफरोज के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।

दुबई में रहकर अपना गिरोह चलाता है शारिक साटा

साटा ने अपने तीनों गुर्गों को हथियार उपलब्ध कराए थे। इसकी जानकारी भी गुर्गों ने पूछताछ में दी थी। मालूम हो शारिक साटा दुबई में रहकर अपना गिरोह चलाता है। वह देश का बड़ा वाहन चोर है। इसके अलावा हथियार, सोना और नकली नोट की तस्करी करने के आरोप भी उस पर लग चुके हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहा था। दिल्ली में मामला दर्ज है। अब संभल पुलिस के रिकॉर्ड में भगोड़ा घोषित है।

एसआईटी की जांच में शारिक साटा और उसका गिरोह आया सामने

संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पांच लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी। इसमें चार ही हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। जबकि पांचवें मृतक के परिजनों ने कार्रवाई से इनकार कर दिया था। बवाल में पुलिसकर्मियों पर भी गोलियां चली थीं। एसआईटी का गठन किया गया तो जांच आगे बढ़ी।

जांच में जामा मस्जिद के पिछले हिस्से वाली गली में मेड इन पाकिस्तान और अमेरिका के खोखे बरामद हुए। इससे जांच का एंगल ही घूम गया। जांच में विशेषज्ञ टीम को भी लगाया गया। सर्विलांस टीम और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी तो शारिक साटा गिरोह प्रकाश में आया। मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस की गिरफ्तारी के बाद वह हथियार भी बरामद हो गए जो शारिक साटा ने उपलब्ध कराए थे। एसपी का कहना है कि बवाल में पुलिसकर्मियों की हत्या की साजिश रची गई थी। जिससे शहर का पूरी तरह माहौल खराब हो जाए और कर्फ्यू लग जाए।

विदेश में बैठकर पूरी साजिश रची गई और इसके बाद ही हथियार उपलब्ध कराए गए थे। यह राज खुलने के बाद ही शारिक साटा को बवाल का साजिशकर्ता माना गया और कार्रवाई आगे बढ़ती गई। अब कुर्की की कार्रवाई के साथ भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।

धर्म गुरुओं के अपमान पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, जुलूस निकालकर किया जोरदार प्रदर्शन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिपीठ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ प्रशासन द्वारा की गई कथित मारपीट व गाली-गलौज की घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सरकार की खुली संरक्षण में प्रशासन की बर्बरता के विरोध में बुधवार को कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व व शहर अध्यक्ष शकील अंसारी की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर व नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सडक पर बैठकर घण्टों नारेबाजी की व दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन औरपूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि जगतगुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी भगवान शंकर के आंशिक अवतार माने जाते हैं उनसे बड़ा कोई हिंदू धर्म में नहीं है ऐसे हमारे सम्मानित धर्मगुरु के साथ मारपीट और अपमान करना यह साबित करता है कि यह सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतर आई है। प्रशासन सत्ता के नशे में चूर होकर संतों पर भी लाठियां चला रहा है। कांग्रेस इस अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। वही उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि भाजपा सरकार में न तो धर्म सुरक्षित है, न ही धर्मगुरु है।शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने कहा कि धर्मगुरुओं का अपमान पूरे हिन्दू समाज का अपमान है, दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से जुलूस निकालकर लाल डिग्गी चौराहा, सुपर मार्केट बड़ा डाकखाना चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क पर बैठकर जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सलाउद्दीन हाशमी, राजेश तिवारी, वरुण मिश्रा, सुब्रत सिंह सनी, ममनून आलम, आवेश अहमद,जफर खान, रणजीत सिंह सलूजा, सियाराम तिवारी, राहुल त्रिपाठी, शरद श्रीवास्तव, श्रीमती राम कुमारी,हमीद राइनी,अतहर नवाब,मो. कमर खान, अशोक सिंह, मनीष तिवारी, नंदलाल मोर्य, मोहित तिवारी, देवेंद्र तिवारी, संतोष वर्मा, मनीष तिवारी, मो. अतीक,मोहसिन सलीम, सियाराम वर्मा,दिनेश तिवारी, इन्द्रकेश शर्मा, सर्वेश सिंह सोनू, राहुल मिश्र, एजाजुद्दीन, राम लौट यादव आदि कांग्रेस नेता व पदाधिकारी शामिल रहे।

12 साल में 8 तबादले... अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले संभल जज विभांशु के लिए ट्रांसफर कोई नई बात नहीं

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। उत्तर प्रदेश का संभल पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में होने की कई वजहें रही हैं। पहले यहां हुई हिंसा और बाद में हुई कार्रवाई भी चर्चा की वजह बनी रही है। अब यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का ट्रांसफर हो गया है। यही वजह है कि एक बार फिर संभल फिर चर्चा में आ गया है। खास बात यह है कि विभांशु सुधीर वही जज हैं जिन्होंने 9 जनवरी को ASP अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। अब संभल का नया CJM आदित्य सिंह को बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मंगलवार शाम को एक लिस्ट जारी

की गई थी। इस लिस्ट में 14 जजों के ट्रांसफर किए गए हैं। कुछ जजों की जगह अदला-बदली भी की गई है। सबसे चौंकाने वाला नाम इस लिस्ट में संभल के सीजेएम का था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह 9 जनवरी के बाद से ही चर्चा में बने हुए थे। सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था ASP अनुज चौधरी समेत अन्य 20 अन्य पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाए। सभी पर आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान उन्होंने एक युवक को गोली मार दी थी। इस आदेश के बाद से ही संभल सीजेएम चर्चा में बने हुए थे।

कौन हैं विभांशु सुधीर?

विभांशु सुधीर मूलरूप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 अगस्त साल 1990 को हुआ था। उन्होंने साल 2004 में अपना हाईस्कूल पूरा किया था। इसके बाद 2011 में एलएलबी कंप्लीट की थी। विभांशु को साल 2013 में पहली बार सुल्तानपुर में पोस्टिंग मिली थी। यहां वे एडिशनल सिविल जज के तौर पर अपॉइंट हुए थे। उन्होंने अब तक यूपी के कई जिलों में काम किया है। इनमें एटा, मुरादाबाद, चंदौली, गाजियाबाद, ललितपुर, आगरा, संभल जैसे जिले शामिल हैं। इस समय वे सीजेएम हैं। वे अब तक संभल में ही अपना काम कर रहे थे। हालांकि अब विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया हैं। वहीं चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया CJM नियुक्त किया गया।

आदित्य सिंह को दिया गया प्रमोशन

संभल के मौजूदा सीजेएम को ट्रांसफर कर सुल्तानपुर भेजा गया है। वहीं आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम नियुक्त किया है। उन्होंने ही श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। उन्हें प्रमोशन के तहत संभल भेजा गया है। आदित्य मूलरूप से यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। उनकी पहली पोस्टिंग बतौर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सहारनपुर में हुई थी।

श्री बाबा जंगली नाथ धाम से निकली भव्य कलश शोभायात्रा, शिवमय हुआ इलाका

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के दावतपुर वलीपुर गांव स्थित श्री बाबा जंगली नाथ महादेव धाम से बुधवार को भव्य कलश शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत इस शोभायात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया,जबकि बड़ी संख्या में पुरुष श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल रहे। डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों और हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा।सुबह 11 बजे से पहले प्रारंभ हुई कलश यात्रा धाम से निकलकर वलीपुर बाजार, दावतपुर, वलीपुर गांव,असरखपुर, पूरे सिधई भगत और पूरे जोधी होते हुए आदि गंगा मां गोमती के मिठनेपुर घाट पहुंची। यहां माताओं व बहनों ने गोमती नदी से पवित्र जल भरा और पुनः श्री बाबा जंगली नाथ महादेव धाम के लिए प्रस्थान किया।शोभायात्रा में आगे-आगे चल रहे सूर्यपुत्र घोड़े ने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया।

यात्रा मार्ग पर जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की सहभागिता से आयोजन और भी भव्य रूप लेता नजर आया।शोभायात्रा को सफल बनाने में समाजसेवी जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू मिश्रा,पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रहरी,भाजपा नेता अवधेश दुबे, राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, पवन सिंह, संदीप जायसवाल, जगदेव आनंद गिरि, रामदीन तिवारी, विनीत तिवारी, जगदेव शास्त्री, अमन वर्मा, प्रदीप यादव, अजय सिंह, संतोष गिरी, गुड्डू गिरी, दिनेश जायसवाल, दिनेश मिश्र, मोनू पांडेय, सुंदरलाल जायसवाल, परशुराम मिश्रा, प्रदीप पांडेय, कृपा शंकर वर्मा, साधु मिश्रा, मनोज मिश्र, प्रदीप सिंह, अमरजीत यादव, सुनील सिंह, वेद प्रकाश तिवारी, अमित मिश्रा, राम अवध यादव, जगन्नाथ पांडेय, राज नारायण पांडेय, राम सिंह गुप्ता, नवनीत अग्रहरि, लव जायसवाल, शिवम जायसवाल, राधे गौड़, अर्जुन गौड़, विनोद तिवारी, अशोक तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।

12 दिन का था बेटा, बुखार से हो गया दिव्यांग... 12 साल से झेल रहा दर्द, आपबीती सुना फफक पड़ी मां

आर्यावर्त संवाददाता

गाजीपुर। गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक के हरिहरपुर गांव के चौथीराम का इकलौता बेटा शिवम 12 वर्ष का है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता है, कमर के नीचे का हिस्सा व पैर सूख चुके हैं। वह मानसिक रूप से कमजोर है। सिर्फ इशारों को समझता है। मां शर्मिला ने बताया कि दो बेटियां और एक बेटा है, लेकिन बेटा शिवम जब 12 दिन का था, उस समय बुखार आया था। इसके बाद झटके आने लगे। इसके बाद दिव्यांगता का शिकार हो गया। बेटे को असहाय हालत में देखकर मां शर्मिला फफक पड़ती हैं। यह दर्द सिर्फ शिवम और उनकी मां शर्मिला का ही नहीं है, बल्कि जिले के 11 गांवों के 43 बच्चे और युवा ऐसे हैं, जो इस तरह की दिव्यांगता झेल रहे हैं।

जिले के ब्लॉक सदर, मनिहारी व देवकली के बहादीपुर, हरिहरपुर, हाला, शिकारपुर, धारीकला, तारडीह,

भौरहा, बुढ़नपुर, राठौली सराय, खिजीरपुर और खुटहन गांव में यह बीमारी करीब 15 साल पुरानी है। मंगलवार को संवाद न्यूज एजेंसी की टीम बहादीपुर, हाला, हरिहरपुर और चौहान बस्ती पहुंची और पीड़ितों का दर्द जाना।

शहर से करीब 12 किमी दूर सदर ब्लॉक के फत्तेहउल्लाहपुर के बहादीपुर मौजा गांव की रमिता देवी ने बताया कि बेटी सोनी तीन वर्ष तक ठीक थी। एक दिन अचानक बुखार आया और बेहोश हो गई। वाराणसी में डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसके दिमाग की नस फट चुकी है। वह मानसिक रूप से कमजोर हो गई। उसके हाथ और पैर टेढ़े हो गए। उनकी बेबसी आंखों से झलक रही थी। कहा कि पति के निधन के बाद अब इतना पैसा नहीं है, जिससे बेटी का उपचार कराया जा सके। इस समय बेटी की उम्र 18 साल के आसपास है, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। उसके भविष्य की चिंता सता रही है।

पड़ोस की पुनसा देवी ने बताया पोती सोनी जब दो साल की थी, तब बुखार आया था। इसके बाद उसके दोनों पैर सूख गए। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सोनी के पिता राम विलास और मां मीरा ईंट-भट्ठे पर काम करते हैं। कुछ दूरी पर रहने वाली गायत्री बताती हैं, उनके पांच बच्चे हैं, दो पुत्र और तीन पुत्रियां। सलोनी तीसरे नंबर पर है। करीब पांच वर्ष की उम्र में उसे बुखार आया था। वाराणसी उपचार कराने ले गई, मगर फायदा नहीं मिला। इलाज पर तीन लाख रुपये खर्च हो गए। सलोनी की तकलीफ को बयां करते-करते उनकी आंखें भर आईं।

गाजीपुर, लखनऊ, वाराणसी ही नहीं उत्तराखंड तक कराया उपचार

हरिहरपुर गांव से कुछ दूरी पर हरिहरपुर चौहान बस्ती है। यहां दो बहनें प्रिया और परिधि भी दिव्यांगता का दंश झेल रही हैं। मां सुभावती देवी कहती हैं कि तीन बच्चे हैं, पुत्र बड़ा है और दोनों बेटियां छोटी हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। चिकित्सक कहते हैं कि ठीक हो जाएगी लेकिन कब ये पता नहीं। बच्चियों का गाजीपुर से लेकर वाराणसी, लखनऊ और उत्तराखंड तक उपचार कराया। वर्तमान में वाराणसी में दोनों बच्चियों का उपचार चल रहा है। पहले झटका बार-बार आता था। अब माह के एक-दो बार आ रहा है। इसी तरह रमिता देवी, गायत्री देवी और पुनसा ने बताया कि वह अपने बच्चों को इलाज कराते कराते थक चुकी हैं।

फसल बीमा के नाम पर मजाक: इंश्योरेंस कंपनी ने कमाए 9.5 करोड़, बाबूराम को क्लेम मिला 2.72 रुपये

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। बरेली जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहेड़ी के बाबूराम को 2.72 रुपये का क्लेम मिला। अखा गांव के सुरेश गंगवार को 3.76 रुपये क्षतिपूर्ति मिली है। ऐसे कई किसान हैं, जिन्हें 100 रुपये से भी कम क्लेम मिला है। इसके विपरीत, सेवा प्रदाता कंपनी इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने 9.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। इसमें किसानों के प्रीमियम के 3.84 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। शेष धनराशि केंद्रांश और राज्यांश की है।

अखा गांव के सुरेश गंगवार ने बताया कि उनके पास ढाई एकड़ खेती है। डेढ़ एकड़ में उन्होंने धान की फसल लगाई थी, जो बाढ़ से तबाह हो गई थी। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर 2.80 लाख रुपये

का लोन लिया था, जिसे वह अदा नहीं कर पाए हैं। फसल बीमा के नाम पर कितना प्रीमियम कटा, बैंक वालों ने इसकी कोई जानकारी या रसीद नहीं दी। उनके बैंक खाते में क्षतिपूर्ति के 3.76 रुपये आए हैं।

वर्ष 2024-25 के खरीफ सीजन में 1,188 किसानों को क्लेम मिला है। इसमें भदपुरा ब्लॉक के फुलवईया के महेंद्रपाल को सर्वाधिक 76,289 रुपये का क्लेम मिला है। इनके पास 50 बीघे खेती है। 20 बीघे में धान की फसल थी जो बाढ़ से नष्ट हो गई थी। नुकसान के मुताबिक क्षतिपूर्ति नहीं मिलने की शिकायत महेंद्र भी कर रहे हैं।

बहेड़ी के जाम अंतरामपुर के बाबूराम की धान की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन उन्हें क्लेम के नाम पर 2.72 रुपये ही मिले हैं। रामनगर के मऊचंदपुर निवासी इदरीश को 2.65 और चंद्रप्रकाश को 2.82 रुपये मिले हैं।

सिर्फ 6,800 किसानों ने कराया गेहूं की फसल का बीमा

इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के जिला समन्वयक दीपक पटेल ने बताया कि रबी सीजन 2025-26 में 18,500 गाटों पर लगी गेहूं की फसल का बीमा किया गया है। बीमित क्षेत्रफल 4,237 हेक्टेयर है। इसमें 6,800 किसानों की फसलों को शामिल किया गया है।

रबी सीजन में भी यही हाल

वर्ष 2024-25 के रबी सीजन में 932 किसानों को क्लेम मिला है। इनमें क्यारा के गांव सिमरा बोरी के अशोक को 3.05, बभिया के कलक्टर सिंह को 3.52, सुरेश कुमार को 4.15 और रमेश चंद्र को 5.40, भोजीपुरा के घंघौआ घनघोरी के रहीस खां को 7.27 रुपये मिले है। बहेड़ी के फिरोजपुर निवासी जीत सिंह को सर्वाधिक 32,318 रुपये मिले हैं। इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के जिला समन्वयक दीपक पटेल ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में क्रॉप कटिंग के जरिये निर्धारित उपज से कम उत्पादन होने पर उसी हिसाब में किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। यही कारण है कि किसी को दो रुपये तो किसी को अधिक धनराशि मिली है। खरीफ 2025 का क्लेम वितरित होना अभी बाकी है।

उप निदेशक कृषि हिमांशु पांडेय ने बताया कि इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस को शासन स्तर से तीन साल का टेंडर मिला है। यह इनके टेंडर का अंतिम वर्ष है। इन्होंने केवल 6,800 किसानों की फसल का बीमा किया है। स्पष्ट है कि ये लोग योजना के प्रति संजीदा नहीं हैं। इंश्योरेंस कंपनी के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखेंगे।

वर्ष 2023 से 2025 तक बीमा कंपनी की कमाई

फसल सत्र	प्रीमियम	क्लेम
खरीफ-2023	2,22,40,096	25,75,733
रबी-2023-24	1,47,24,751	17,10,712
खरीफ-2024	1,88,80,476	23,94,658
रबी-2024-25	1,92,91,812	27,86,676
खरीफ-2025	1,99,21,819	अभी बाकी

ये भी जानें

प्रति हेक्टेयर धान की फसल पर 1,610 तो गेहूं की फसल के लिए 1,212 रुपये प्रीमियम किसान को देना होता है।

स्व. ठा. इंद्रभद सिंह की 27वीं पुण्यतिथि श्रद्धा व सेवा भाव के साथ मनाई गई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं सम्मानित व्यक्तित्व स्वर्गीय ठाकुर इंद्रभद सिंह की 27वीं पुण्यतिथि आज अत्यंत श्रद्धा, आस्था और सामाजिक सेवा भाव के साथ मनाई गई। यह अवसर उनके जीवन, व्यक्तित्व और समाज के प्रति दिए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करने का भावुक क्षण रहा। पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक आवास 'इंद्रप्रस्थ' में अथर्ववेद ब्रह्मपारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के बीच पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहा। इस महायज्ञ में चंद्रभद्र सिंह 'सोनू', यशभद्र सिंह 'मोनू' सहित भद्र परिवार के सभी सदस्य श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित हुए। पुण्यतिथि के मौके पर बड़े पैमाने पर कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर मानवता और सेवा का संदेश दिया गया। वहीं आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न समुदायों के लोगों ने एकत्र होकर स्व. ठाकुर इंद्रभद सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शुभचिंतकों का भारी जनसैलाब उमड़ा। इसके साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों के नेताओं की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। भद्र परिवार की ओर से आगंतुकों के लिए बैठने, खाने-पीने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित किया गया। पूरे आयोजन में श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समर्पण की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिली, जिससे स्व. ठाकुर इंद्रभद सिंह की स्मृतियां एक बार फिर जनमानस में जीवंत हो उठीं।

सीएम योगी बोले- 'एक जनपद-एक व्यंजन' होगा इस वर्ष का प्रमुख आकर्षण, हर जिले के स्वाद से परिचय कराएगा...

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

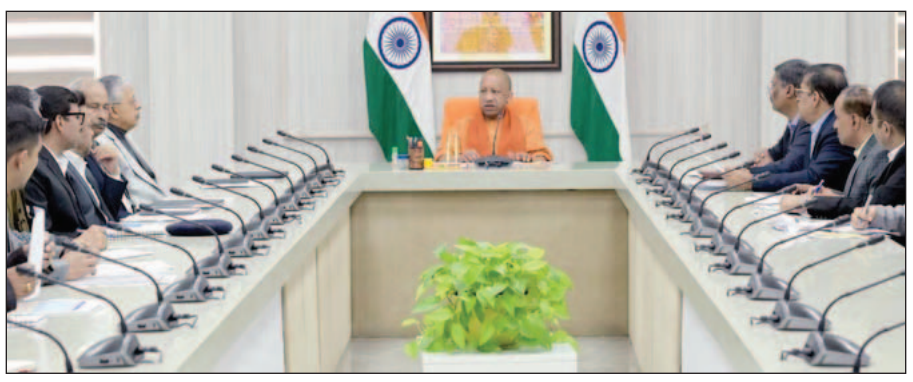

लखनऊ। प्रदेश के प्रत्येक जनपद की सक्रिय सहभागिता, सांस्कृतिक विविधता और विकास की साझा चेतना के साथ उत्तर प्रदेश दिवस-2026 इस वर्ष एक भव्य जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 24 से 26 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को जनभागीदारी के माध्यम से एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश की पहचान, उपलब्धियों और संभावनाओं को जनसहयोग के साथ प्रदर्शित करने का अवसर है। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश दिवस को जनोत्सव के रूप में आयोजित किया जाए, जिसमें प्रदेश की आत्मा हर स्तर पर दिखाई दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान प्रदान करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं गरिमा, अनुशासन एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित की जाएं।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जनपदों में किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश दिवस का उत्सव एक साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा सके। बैठक में अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' की थीम पर आधारित विशेष प्रदर्शनी और शिल्प मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की विकास यात्रा, नवाचार, बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

इस वर्ष 'एक जनपद-एक व्यंजन' को आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजन एक ही परिसर में उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आगंतुक उत्तर प्रदेश के विविध स्वाद, खान-पान परंपराओं और स्थानीय पहचान से परिचित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संस्कृति उत्सव 2025-26 के अंतर्गत प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश दिवस से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि 'हमारी संस्कृति-हमारी पहचान' की भावना के अनुरूप लोक, शास्त्रीय एवं समकालीन कला रूपों को मंच प्रदान किया जाए तथा कलाकारों एवं आगंतुकों के लिए समुचित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 24 जनवरी को आयोजित मुख्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी जनपदों के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाए, ताकि प्रदेश की सामूहिक उपलब्धियों का सम्मान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस-2026 को ऐसा आयोजन बनाया जाए, जो प्रदेश की संस्कृति, स्वाद, शिल्प और विकास दृष्टि को एक साथ प्रस्तुत करे तथा प्रत्येक आगंतुक के लिए यह अनुभव प्रेरणादायी, स्मरणीय और गर्व का विषय बने।

पूर्वांचल विकास निधि से आजमगढ़ की चार परियोजनाओं को 71.76 लाख की मंजूरी, ग्रामीण विकास को मिलेगी गति

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत जनपद की चार विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 71 लाख 76 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्रेषित कर दी गई है।शासनादेश के अनुसार इन विकास कार्यों के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, जो स्वीकृत परियोजनाओं को तय मानकों और समयसीमा के भीतर पूर्ण कराएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई है, तथा किसी अन्य मद में व्यय की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यय स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर ही रखा जाएगा।जनपद आजमगढ़ की जिन ग्राम सभाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, उनमें ग्रामसभा सोनौरा के लिए 12.28 लाख रुपये, ग्रामसभा दिघवनिया के लिए 23.09 लाख रुपये, ग्रामसभा जहिरूद्दीनपुर के लिए 15.43 लाख रुपये तथा ग्रामसभा सोखना खालसा के लिए 20.96 लाख रुपये की धनराशि शामिल है। इन परियोजनाओं के माध्यम से संबंधित ग्राम सभाओं में बुनियादी सुविधाओं के विकास और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।प्रदेश सरकार का यह निर्णय पूर्वांचल क्षेत्र के संतुलित विकास की नीति को मजबूती प्रदान करता है। विकास निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना सुदृढ़ होगी।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत, लखनऊ की दो पंचायतों से शुरू हुई आधार सेवाएं

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप और पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रहा है। इसी क्रम में ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत करते हुए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक डिजिटल पहल को धरातल पर उतारा गया है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को सीधे अपने गांव में ही महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है।प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्लॉक सरोजनीनगर की ग्राम पंचायत भटगनवां पांडेय तथा चिनहट ब्लॉक की सैरपुर ग्राम पंचायत में आधार सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दी गई हैं। इन दोनों ग्राम पंचायतों में अब तक 40 से अधिक ग्रामीण नागरिकों को आधार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इस सुविधा के शुरू होने से ग्रामीणों को अब आधार अपडेट, संशोधन और अन्य सेवाओं के लिए शहरों या दूरस्थ केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है।पंचायती राज विभाग की यह पहल पंचायत स्तर पर नागरिक सेवाओं की सहज, पारदर्शी और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम मानी जा रही है। विभाग की योजना के अनुसार पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके बाद इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा, ताकि हर गांव के नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का सीधा लाभ मिल सके।इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायकों का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अब तक 800 से अधिक पंचायत सहायकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि शेष पंचायत सहायकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रशिक्षित पंचायत सहायक ग्राम स्तर पर नागरिकों को आधार सेवाएं उपलब्ध कराकर पंचायतों को एक सशक्त सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।इस अवसर पर पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल न केवल समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अंतिम व्यक्ति की आवाज को सदन तक पहुंचाने की प्रेरणा हमारी संसद है, सम्मेलन को किया संबोधित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को सदन में पहुंचाने की प्रेरणा हमारी संसद है। जो भी विधानसभा संसद के नियमों का अवलोकन कर ले तो उसे अपनी विधानसभा चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के विधान भवन में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित रहे थे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर संसद की तर्ज पर नियमावली में बदलाव किये गए हैं जिससे अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सदन में होती है। विधानसभा में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश , आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संबंध में एक विस्तृत चर्चा हुई है। इस चर्चा में 300 से अधिक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे सदन की कार्यवाही आराम से होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में पेपर लेस काम बड़े स्तर पर होता है। यूपी विधानसभा लगातार देश के अलग-अलग ज्वलन्त मुद्दों पर चर्चा करती रहती है। 26 नवम्बर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने मौलिक अधिकारों को लेकर दोनों सदनों में चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह मंच सीखने और सिखाने के लिए है। यह कार्यक्रम एक नई प्रेरणा है।

संक्षेप

21 जनवरी, 2026उत्तर प्रदेश की 14 लखपति दीदियां गणतंत्र दिवस परेड में करेंगी प्रतिभाग

लखनऊ। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी उत्तर प्रदेश की 14 लखपति दीदियां और उनके सहयोगी 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के कर्त्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इन दीदियों को 23 जनवरी को उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अपने कैम्प कार्यालय, 7-कालिदास मार्ग, लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा।मिशन निदेशक श्रीमती दीपा रंजन ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड से पूर्व ये दीदियां भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में माननीय मंत्री श्री शिव राज सिंह चौहान से भेंट करेंगी और अन्य राज्यों की दीदियों के साथ दिल्ली भ्रमण भी 27 जनवरी को करेंगी। उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस परेड में गरीब एवं मेहनती महिलाओं को शामिल करना उत्तर प्रदेश और देश के लिए गौरव की बात है।

उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए प्रत्यायन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों की ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और कुशल चालकों को ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (मोर्थ) ने प्रत्यायन (प्रमाणन) प्राप्त चालन प्रशिक्षण केन्द्र (एडीटीसी) की स्थापना और उसके क्रियान्वयन के संबंध में केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े हैं। इसका मुख्य लक्ष्य चालन प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से संचालित करना है।परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रत्यायन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए आवेदन अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रणाली से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सभी आवश्यक अभिलेख डिजिटल माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। पहले इस प्रक्रिया के लिए ऑफलाइन आवेदन व्यवस्था थी, जिसे अब पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। विभाग इस पोर्टल को जल्द ही लाइव करने की तैयारी में है।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 58 जनपदों में (आईडीटीआर एवं डीटीटीआई को छोड़कर) प्रत्यायन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए अब आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। 10 लाख की आबादी पर एक प्रत्यायन प्रशिक्षण चालन केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में 18 जनपदों में 21 सेंटर संचालन में हैं।

उत्तर प्रदेश में कृषि विकास और शिक्षा को मिले वित्तीय प्रोत्साहन, किसानों और छात्र-छात्राओं को मिले लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, कृषकों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने और कृषि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इन स्वीकृतियों से न केवल किसानों को सिंचाई और कृषि लागत में मदद मिलेगी, बल्कि कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी।कृषि उत्पादन में वृद्धि के संकल्प के अनुरूप, शासन ने कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को जनवरी 2026 से मार्च 2026 की अवधि के लिए 60,000.00 लाख रुपये (छः अरब रुपये) की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस धनराशि का उपयोग किसानों को विद्युत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अधीन संचालित कृषि महाविद्यालय, हरदोई परिसर में 75 कमरों के आधुनिक बालक छात्रावास के निर्माण हेतु 1832.12 लाख रुपये (अट्ठारह करोड़ बत्तीस लाख बारह हजार रुपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

बौद्ध संगम माघ मेला का शुभारंभ, शांति-करुणा और सामाजिक सद्भाव का संदेश देगा आयोजन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित बौद्ध संगम माघ मेला का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को आयोजित उद्घाटन सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बौद्ध परंपरा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखते हुए आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।उद्घाटन सत्र में विश्व हिंदू परिषद के अशोक तिवारी ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के निदेशक डॉ. राकेश सिंह, संस्थान के माननीय सदस्य देवानंद वर्धन, संस्थान के कर्मचारी, बौद्ध भिक्षु और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पण के साथ की गई, जिसके बाद बौद्ध परंपराओं से जुड़े सांस्कृतिक भावों को साझा किया गया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक तिवारी ने कहा कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आज भी समाज को शांति, करुणा और मानवीय मूल्यों की दिशा दिखाती हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से बौद्ध संस्कृति और दर्शन का संरक्षण व प्रसार होता है, जो सामाजिक समरसता और आपसी सद्भाव को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है।संस्थान के निदेशक डॉ. राकेश सिंह ने अपने संबोधन में बौद्ध संगम माघ मेले के उद्देश्य, कार्यक्रमों और सामाजिक-सांस्कृतिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान बौद्ध दर्शन, संस्कृति और परंपरा से जुड़े विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य समाज में शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है।उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बौद्ध संगम माघ मेला 1 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और बौद्ध दर्शन से संबंधित गतिविधियां होंगी। यह आयोजन शांति, करुणा, सद्भाव और सामाजिक एकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा।

21 जनवरी, 2026अटल आवासीय विद्यालयों में कौशल प्रशिक्षण को लेकर BOCW योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ। मिशन निदेशक श्री पुलकित खरे की अध्यक्षता में आज भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के सत्यापन और प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत अटल आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीओसीडब्ल्यू योजना के तहत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और योजनाओं के पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। मिशन निदेशक श्री पुलकित खरे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित समय में योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

मिशन शक्ति के तहत मदेयगंज में महिला सशक्तिकरण का व्यापक अभियान, खदरा चुंगी और त्रिवेणी नगर में महिलाओं-बच्चों को किया गया जागरूक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 21 जनवरी 2026 को थाना मदेयगंज क्षेत्र के खदरा चुंगी और त्रिवेणी नगर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य गली-मोहल्लों तक महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाना और महिलाओं, छात्राओं व बच्चों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों के प्रति सजग करना रहा।मदेयगंज थाना की पिंक स्कूटी और एंटी-रोमियो टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं से सीधे संवाद किया। टीम ने महिला अपराधों की रोकथाम, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण और साइबर अपराध जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही आपात परिस्थितियों में सहायता के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की गई, जिनमें विमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आपातकालीन सेवा 112, साइबर हेल्पलाइन 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 शामिल हैं। जागरूकता के लिए संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए।अभियान के दौरान पिंक बूथ, पिंक मोबाइल और महिला शक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तार से बताया गया। महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या संकट की स्थिति में वे बिना झिझक इन संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं। पुलिस टीम ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किया।गौरतलब है कि मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में लखनऊ कमिश्नरेट के 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों पर निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है, ताकि थानों पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का त्वरित और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित किया जा सके। पिंक बूथ पहल को प्रदेश सरकार द्वारा हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जो उन्हें एकीकृत समर्थन प्रदान करती है।इस जागरूकता अभियान में महिला उपनिरीक्षक सविता सिंह, महिला हेड कांस्टेबल पूनम, वर्तिका चतुर्वेदी और ज्योति सहित पुलिस टीम के सदस्य सक्रिय रूप से शामिल रहे। टीम ने राहगीरों से संवाद कर यह भरोसा दिलाया कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस सदैव तत्पर है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

युवाओं के कौशल और स्वरोजगार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया "कौशल दिशा" पोर्टल

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने की दिशा में "कौशल दिशा" पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल राज्य में कौशल विकास की व्यापक और समावेशी नीति का डिजिटल माध्यम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल अंतर को समाप्त कर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है।प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि "कौशल दिशा" पोर्टल योगी सरकार की उस सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत युवाओं को कौशल, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जाता है। यह एक ऑनलाइन कौशल शिक्षा मंच है।

21 जनवरी, 2026राजकीय नलकूपों और पम्प नहरों की सतत क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज उदयगंज स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के राजकीय नलकूपों एवं पम्प नहरों की सतत क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से रबी और खरीफ फसलों की सिंचाई के समय किसी भी प्रकार की बाधा न आए।बैठक में प्रदेश के यांत्रिक संगठन द्वारा संचालित राजकीय नलकूपों, लघु डाल नहरों और वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों के संचालन, अनुरक्षण और अनुश्रवण की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रदेश में कुल 36,094 राजकीय नलकूप हैं, जिनसे लगभग 30.06 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 257 लघु डाल नहरों और 30 वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों के माध्यम से क्रमशः 1.88 लाख हेक्टेयर और अन्य क्षेत्रों में सिंचाई की जा रही है। विगत आठ वर्षों में कुल 291 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 7.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन/पुनर्स्थापन हुआ है, जिससे 7.44 लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं श्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नलकूपों और पम्प नहरों के संचालन और अनुरक्षण में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए गए प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, फील्ड से प्राप्त फीडबैक के आधार पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

पीजीआई क्षेत्र में युवक प्रदीप सिंह परिहार की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। दक्षिणी जोन अंतर्गत थाना पीजीआई क्षेत्र में युवक प्रदीप सिंह परिहार की नृशंस हत्या के मामले का पुलिस ने कुछ ही घंटों में सफल अनावरण करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। धारदार हथियार से की गई इस हत्या की साजिश मृतक की पत्नी पूजा सिंह ने अपने प्रेमी रामतीर्थ मौर्या के साथ मिलकर रची थी। पीजीआई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू तथा घटना के समय पहनी गई टी-शर्ट भी बरामद कर ली है।पुलिस के अनुसार 21 जनवरी 2026 को वादी लखन सिंह द्वारा थाना पीजीआई पर अपने पुत्र प्रदीप सिंह परिहार की हत्या की सूचना देते हुए लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 45/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस के अंतर्गत पूजा सिंह और रामतीर्थ मौर्या के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया और लगातार दबिश के बाद कुछ ही घंटों के भीतर घटना का खुलासा करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार अभियुक्तों में रामतीर्थ मौर्या पुत्र शेषनाथ मौर्या उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम हवेली पोस्ट जमरवा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी, हाल पता संदीप पाल का किराये का मकान उतरेठिया थाना पीजीआई लखनऊ शामिल है। वहीं दूसरी अभियुक्ता पूजा सिंह पत्नी प्रदीप सिंह परिहार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम अमौली ठाकुरान थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, हाल पता संदीप पाल का किराये का मकान उतरेठिया थाना पीजीआई लखनऊ है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक अदद चाकू और एक टी-शर्ट बरामद की है।पूछताछ के दौरान अभियुक्त रामतीर्थ मौर्या ने बताया कि वह संदीप पाल के किराये के मकान में पूजा के बगल में ही रहता था और पूजा से प्रेम करता था। इसी दौरान उसकी मृतक प्रदीप सिंह परिहार से दोस्ती हो गई थी। पूजा और उसके पति के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि प्रदीप अत्यधिक शराब का सेवन करता था। इसी बात से परेशान होकर पूजा ने रामतीर्थ के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पूजा ने अपने पति के कानपुर देहात से लखनऊ आने की जानकारी पहले ही रामतीर्थ को दे दी थी और उसे हत्या के लिए उकसाया था।पूजा के कहने पर ही रामतीर्थ ने शाम को प्रदीप को शराब पिलाकर हत्या करने की योजना बनाई। दोनों प्लेटिना मोटरसाइकिल संख्या UP 32 KE 1918 से शराब पीने निकले थे। शराब पीने के बाद जब प्रदीप मोटरसाइकिल चला रहा था और रामतीर्थ पीछे बैठा था, उसी दौरान चिरैय्याबाग अंडरपास के पास सर्विस लेन पर पहले से बनाई गई योजना के तहत रामतीर्थ ने अपनी जींस में छिपाकर रखे चाकू से प्रदीप सिंह परिहार का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।

विकास के नाम पर सिर्फ बढ़ता प्रदूषण

एक पुरानी कहावत है, 'खाया पिया कुछ नहीं गिलास फोड़ा बारह आना।' प्रदूषण के मामले में वही हाल भारत का है। लंदन से लेकर बीजिंग तक दुनिया भर के देशों की राजधानियों और दूसरे शहरों में एक समय प्रदूषण का साया रहा लेकिन वह इसलिए रहा क्योंकि उन देशों और शहरों में औद्योगिक विकास हो रहा था। लंदन में प्रदूषण का संकट पहली औद्योगिक क्रांति के बाई प्रोडक्ट की तरह आया। बाद में इन शहरों ने प्रदूषण दूर भी कर लिया। लेकिन भारत में कोई औद्योगिकीरण नहीं हुआ लेकिन प्रदूषण चौतरफा फैल गया। अगर उद्योग धंधे लगते, औद्योगिक विकास हो रहा होता, चीन की तरह भारत दुनिया की फैक्टरी बन रहा होता, लोगों की आमदनी बढ़ रही होती और उसी अनुपात में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा होता तो हवा के प्रदूषण को समझा जा सकता था। माना जाता है कि देश विकास कर रहा है इसलिए प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। और तब यकीन भी होता कि एक दिन भारत प्रदूषण की समस्या से निजात पा जाएगा।

लेकिन भारत में प्रदूषण की समस्या विकास का बाई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि अव्यवस्था का मुख्य उत्पाद है। भारत में अगर ठीक से सफाई हो जाए तो प्रदूषण की समस्या 20 फीसदी कम हो जाएगी। इसके लिए सड़कों पर सफाई और कचरा उठाने का बंदोबस्त करना होगा। लेकिन वह भी नहीं हो पाता है। स्थानीय प्राधिकरण सफाई नहीं करा पाता है और उलटे अनियमित निर्माण की अनुमति देता है, जिसकी कोई निगरानी नहीं होती है। देश में योजनाबद्ध तरीके से बसे शहरों की गिनती की जाए तो संख्या दो अंकों में नहीं पहुंचेगी। बाकी ऐसे ही गांवों, कस्बों में या सड़कों के किनारे शहर उग आए हैं या शहर फैल कर गांवों और कस्बों तक पहुंच गए हैं, जहां शहर की कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ बेतरतीब तरीके से निर्माण हो रहा है। नदियों और तालाबों को भर कर मकान और दुकान बनाए जा रहे हैं। इसी तरह बेहिसाब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। शहरों में फैली गंदगी और गाड़ियों का धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है।

पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि देश के प्रदूषण में बड़ा योगदान गाड़ियों का है। लेकिन वे क्या कर सकते हैं? सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी दे रही है लेकिन पेट्रोल व डीजल की गाड़ियां ज्यादा सस्ती हैं तो लोग उसे खरीद रहे हैं। दोनों तरह की गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाड़ियों के चलने के लिए सड़क नहीं है और न ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई उपाय है। हर साल सर्दियों में कहा जाता है कि अगर ट्रैफिक रेगुलेट कर दिया जाए और जाम लगना कम हो जाए तो प्रदूषण में कितनी कमी आ सकती है। लेकिन हर साल सर्दियों के साथ जाम भी बढ़ता जाता है और प्रदूषण भी बढ़ता जाता है।

राजधानी दिल्ली या वित्तीय राजधानी मुंबई की बात समझ में भी आती है लेकिन बिहार के बेगूसराय या मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का कोई कारण नहीं है। ये शहर हर साल देश के सबसे प्रदूषित शहरों में जगह पाते हैं। सरकार टियर टू और टियर थ्री के शहरों का विकास करने की बात करती है लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ ट्रैफिक बढ़ता है और प्रदूषण बढ़ता है। बिहार में बिना उद्योग लगे हर शहर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई तीन सौ से ऊपर रहता है। सरकार मान चुकी है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। और लोग भी सर्दियों के बाद भूल जाते हैं।

महाराष्ट्र में भाजपा के विकास एवं विश्वास की निर्णायक जीत

बीएमसी का महत्व केवल राजनीतिक प्रतीकात्मकता तक सीमित नहीं है। यह देश का सबसे धनी नगर निगम है, जिसका 2025-26 का बजट 74,427 करोड़ रुपये का है, जो कई छोटे राज्यों के बजट से भी अधिक है। इसीलिये बीएमसी शिवसेना का आर्थिक संबल थी

ललित गर्ग

महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न शहरी निकाय चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा, प्रवृत्ति और भविष्य का संकेत देने वाला एक बड़ा जनादेश बनकर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। यह बदलाव केवल सत्ता के हस्तांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक सोच, जन अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक व्यवहार में गहरे परिवर्तन का द्योतक है। इन चुनावों ने जहां भगवा राजनीति की वैचारिक और संगठनात्मक शक्ति को नए सिरे से रेखांकित किया है, वही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक सोच एवं विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। यह सफलता ऐसे समय में मिली है जब विधानसभा चुनावों में विपक्ष को करारी शिकस्त दिए जाने को अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बावजूद राज्यव्यापी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा नीत महायुति गठबंधन का दबदबा यह दर्शाता है कि यह जीत क्षणिक नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ राजनीतिक प्रवाह का परिणाम है। इन परिणामों ने राष्ट्र का ध्यान इसलिए अपनी ओर खींचा, क्योंकि इन चुनावों को मिनी विधानसभा चुनावों की संज्ञा दी गई थी। दशकों तक शिवसेना के वर्चस्व का प्रतीक रहे बृहन्मुंबई नगर निगम, यानी बीएमसी में शिवसेना का दशकों पुराना किला ढ़ह गया, बीएमसी एवं राज्यभर के शहरी निकाय चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना एवं उसका दबदबा कायम होना, एक बड़े राजनीतिक बदलाव का सबसे सशक्त प्रमाण है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक सोच और कार्यशैली इस पूरे परिदृश्य में एक निर्णायक कारक के रूप में उभरकर सामने आई है। फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति को केवल सत्ता संतुलन की सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि उसे दीर्घकालिक विकास दृष्टि से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे व्यापक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता, निवेश अनुकूल वातावरण और सुशासन को उन्होंने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। उनकी राजनीति भावनात्मक उत्तेजना या तात्कालिक लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि योजनाबद्ध विकास, प्रशासनिक दक्षता और भविष्य की तैयारी पर आधारित रही है। मुंबई से लेकर विदर्भ और मराठवाड़ा तक विकास की समान अवधारणा, शहरी-ग्रामीण संतुलन और रोजगार सृजन पर जोर उनकी सोच को प्रतिबिंबित करता है। इस महाविजय के पीछे फडणवीस की रणनीति के चार प्रमुख स्तंभ रहे हैं- हिंदुत्व और विकास का संतुलन, लोकल मुद्दों पर फोकस, विपक्ष पर प्रभावी जवाब और जनता के साथ जुड़ाव। यही कारण है कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनता ने उन्हें केवल एक प्रशासक के रूप में नहीं, बल्कि एक दूरदृष्टा नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की जो राष्ट्रीय अवधारणा गढ़ी गई, देवेंद्र फडणवीस ने उसे महाराष्ट्र की राजनीतिक और प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यही दृष्टि महायुति की सफलता की वैचारिक रीढ़ बनती दिखाई देती है।

बीएमसी का महत्व केवल राजनीतिक प्रतीकात्मकता तक सीमित नहीं है। यह देश का सबसे धनी नगर निगम है, जिसका 2025-26 का बजट 74,427 करोड़ रुपये का है, जो कई छोटे राज्यों के बजट से भी अधिक है। इसीलिये बीएमसी शिवसेना का आर्थिक संबल थी, क्योंकि भ्रष्ट तौर-तरीकों के कारण नगर निकाय का पैसा उसके नेताओं के पास पहुंचता था। बीएमसी के इसी भ्रष्टाचार के कारण मुंबई अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित नहीं हो पा रही थी। ऐसे में बीएमसी पर नियंत्रण का अर्थ है नीतिगत प्राथमिकताओं, शहरी विकास की दिशा और संसाधनों के उपयोग पर निर्णायक प्रभाव। भाजपा नेतृत्व वाली महायुति की सफलता यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में मुंबई का प्रशासनिक और विकासात्मक स्वरूप नए सिरे से गढ़ा जाएगा। मुंबई को खराब सडकों, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से त्रस्त शहर की छवि से मुक्त करना भाजपा की पहली प्राथमिकता बननी चाहिए। इन चुनावों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि दो दशक बाद ठाकरे परिवार से जुड़ी पार्टियां एकजुट होकर मैदान में उतरीं, फिर भी वे महायुति की लहर को रोकने में असफल रहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की प्रतीकात्मक एकता मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकी। इसी तरह शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुटों का पूणे में गठबंधन भी बुरी तरह विफल रहा। यह पराजय उन राजनीतिक परिवारों के लिए एक चेतावनी है, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य की राजनीति में वर्चस्व बनाए रखा था।

इन परिणामों से यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता ने क्षेत्रीय संकीर्णता और पुराने नारों की बजाय विकास, स्थिरता और विश्वास की राजनीति को प्राथमिकता दी है। 'मराठी मानुष' जैसे भावनात्मक मुद्दे इस बार ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। मतदाताओं ने यह संकेत दिया है कि वे अपनी आकांक्षाओं को केवल पहचान की राजनीति में सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि वे बेहतर बुनियादी ढांचे, पारदर्शी प्रशासन और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि चाहते हैं। इन स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की हाशिये पर मौजूदगी भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह स्थिति कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का अवसर है। महाराष्ट्र जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में उसकी कमजोर होती पकड़ यह सवाल उठाती है कि क्या पार्टी बदलते राजनीतिक परिदृश्य को समझने और उसके अनुरूप रणनीति बनाने में विफल हो रही है। महा विकास अघाड़ी गठबंधन के भविष्य पर भी इन परिणामों ने प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इसके घटक दल पहले ही प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह पराजय उस संघर्ष को और कठिन बना देती है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ठाकरे और पवार जैसे परिवारों को अब अपनी राजनीति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। केवल विरासत और अतीत की उपलब्धियों के सहारे राजनीति नहीं चलाई जा सकती। जनता अब जवाबदेही, परिणाम और स्पष्ट दिशा चाहती है। इसके विपरीत भाजपा ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह चुनाव जीतने का गणित अच्छी तरह समझ चुकी है। मजबूत बूथ मैनेजमेंट, कैडर आधारित संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक व सांगठनिक संबल उसकी सफलता की आधारशिला बने हैं। यही कारण है कि भाजपा न केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकली, बल्कि कई स्थानों पर अपने सहयोगियों पर भी भारी पड़ी। इन चुनावों का व्यापक अर्थ केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। यह परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक संकेत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास, विकास और आश्वासन की राजनीति को जनता लगातार समर्थन दे रही है। यह राजनीति केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव की अनुभूति कराती है। अंधेरों के बीच रोशनी की किरण की तरह यह राजनीति आम नागरिक को यह विश्वास दिलाती है कि उसका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इससे राजनीतिक परिभाषाएं ही नहीं बदलीं, बल्कि इंसान की सोच में भी परिवर्तन आया है। मतदाता अब भावनात्मक उकसावे से अधिक ठोस उपलब्धियों और संभावनाओं को महत्व देने लगा है।

टिप्पणी

संवैधानिक व्यवस्था दायरे में नहीं

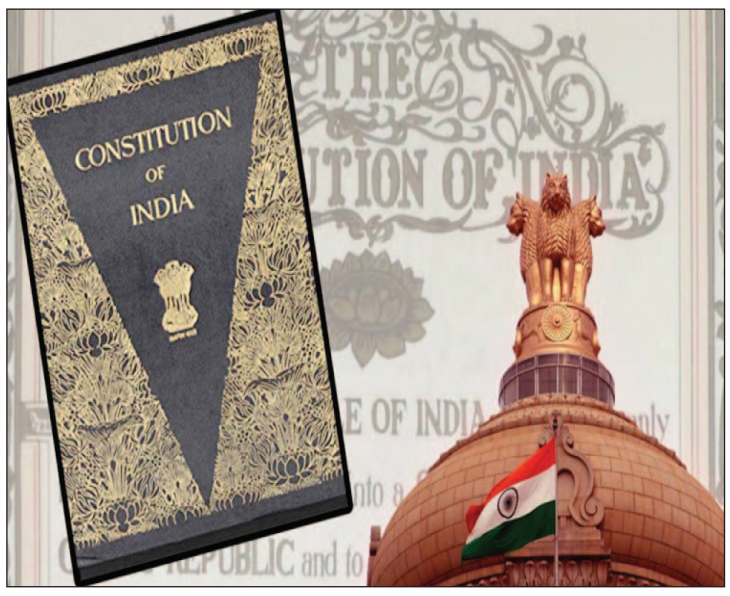

कोलकाता की घटना संघीय ढांचे के चरमराने का संकेत है। संबंधित पक्ष ऐसे विवादों से सड़कों पर निपटने लगें, तो उसका अर्थ है कि बात संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में नहीं रह गई है। आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई?

कोलकाता में आई-पैक के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे का मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर उतर कर किया। ऐसा शायद पहली बार हुआ, जब एक केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के बीच किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का दखल दिया हो। उस घटना के बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ रखा है। उधर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की पनाह ली है। ईडी का इल्जाम है कि आई-पैक एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों ने हवाला के जरिए अवैध रूप से धन का लेन-देन किया है। जबकि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि चूंकि आई-पैक को उसने अपने विधानसभा चुनाव अभियान के प्रबंधन का ठेका दिया है और इसलिए उसके पास पार्टी की रणनीति संबंधी आंकड़े हैं, तो उन्हें ही चुराने ईडी वहां गई थी।

तृणमूल की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने दस्तावेजों की चोरी का केस दर्ज किया है। उसने उन ईडी तथा केंद्रीय शस्त्र बल के कर्मियों की पहचान शुरू कर दी है, जो आई-पैक के दफ्तर पर गए। तो इस रूप में ये मामला केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव में तब्दील हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि तृणमूल ने अपनी शिकायत को बयानों या कानूनी चुनौती तक सीमित नहीं रखा। उसकी नेता एवं मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से ईडी के छापे में रुकावट डाली। यह घटना देश के संघीय ढांचे के चरमराने का संकेत है।

संबंधित पक्ष ऐसे विवादों से सड़कों पर निपटने लगें, तो उसका अर्थ है कि बात संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में नहीं रह गई है। यह गंभीर विचार-विमर्श का विषय है कि ये नौबत क्यों आई? साफ वजह राजनीतिक वर्ग में आपसी भरोसे का टूट जाना है। विपक्षी खेमों में आम धारणा है कि केंद्रीय एजेंसियां सत्ताधारी भाजपा के सियासी मकसद को साधने का औजार बन गई हैं। इस दौर में कानूनों की व्याख्या के क्रम में न्यायपालिका ने भी राजनीतिक परिदृश्य की अनदेखी कर तकनीकी नजरिया अपना रखा है। ऐसे में तृणमूल को सड़क पर मुकाबला करना मुफीद महसूस हुआ होगा। लेकिन लोकतंत्र एवं संघीय व्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है।

ब्लॉग

बंगाल में लोकतंत्र, विकास और अस्मिता की निर्णायक परीक्षा-घड़ी

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां सत्ता, संघर्ष, कानून और जनभावना-चारों धाराएं एक-दूसरे से टकराती हुई दिखाई देती हैं। यह टकराव केवल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भर नहीं है, बल्कि यह उस शासन शैली, लोकतांत्रिक मर्यादा और विकास दृष्टि की भी परीक्षा है, जिसके आधार पर बंगाल अपनी आने वाली राजनीतिक दिशा तय करेगा। लंबे समय तक "खेला होगा" के नारे के सहारे भाजपा को रोकने में सफल रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार परिस्थितियां अपेक्षाकृत अधिक जटिल, चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी नजर आ रही हैं। आज समूचे देश की नजरे पश्चिम बंगाल पर टिकी है। वहां आगामी विधानसभा काफी रोमांचक एवं निर्णायक होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल का नया भविष्य बुनने की दिशाएं उद्घाटित होगी।

एक ओर केंद्र और राज्य के बीच टकराव अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, अदालती टिप्पणियां और कानूनी बहसें राजनीतिक विमर्श को नियंत्रित कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने केवल एक कानूनी प्रश्न ही नहीं उठाया, बल्कि यह संकेत भी दिया कि राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप की सीमाएं कहां तक हो सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी की उस राजनीतिक छवि को आंशिक रूप से प्रभावित किया है, जो अब तक स्वयं को केंद्र के कथित दमन के विरुद्ध संघीय ढांचे की रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती रही हैं। अदालतों में लंबी चलने वाली कानूनी लड़ाइयों का राजनीतिक प्रभाव तुरंत और गहरा होता है, विशेषकर तब, जब चुनाव नजदीक हों और जनता का ध्यान प्रशासनिक उपलब्धियों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप पर केंद्रित होने लगे। बंगाल की राजनीति की एक विशिष्ट विशेषता यह रही है कि यहां विचारधारा और भावनाएं अत्यंत तीव्र रूप से अभिव्यक्त होती हैं। वाम मोर्चे के लंबे शासन के बाद ममता बनर्जी का उदय एक जनांदोलन के रूप में हुआ था। उन्होंने न केवल वामपंथी वर्चस्व को तोड़ा, बल्कि खुद को गरीब, हाशिए के वर्ग और क्षेत्रीय अस्मिता की आवाज के रूप में स्थापित किया। शुरुआती वर्षों में उनकी सरकार ने कुछ कल्याणकारी योजनाओं और सशक्त राजनीतिक संप्रेषण के माध्यम से जनता का विश्वास भी अर्जित किया। किंतु समय के साथ सत्ता का केंद्रीकरण, संगठन पर अत्यधिक नियंत्रण और विरोध के प्रति असहिष्णुता जैसे आरोप भी समानांतर रूप से उभरते गए।

भाजपा ने इन्हीं कमजोरियों को अपना राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश की है। 2019 के लोकसभा चुनावों से लेकर अब तक भाजपा ने बंगाल में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद तथा भ्रष्टाचार विरोधी विमर्श को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से वापसी की, लेकिन यह भी सच है कि भाजपा बंगाल की राजनीति में एक स्थायी और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। मत प्रतिशत में अंतर और सीटों का आंकड़ा भाजपा के लिए भले ही निराशाजनक रहा हो, पर संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक आधार का विस्तार उसके लिए भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोलता है। हाल के वर्षों में बंगाल में विकास का प्रश्न अपेक्षाकृत पीछे छूटता दिखाई दिया है। उद्योग, निवेश और रोजगार के मुद्दे राजनीतिक शोर में दब गए हैं। आम जनता की एक बड़ी चिंता यह भी है कि राज्य की राजनीति निरंतर टकराव और हिंसा के आरोपों से क्यों घिरी रहती है। चुनावी हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले और प्रशासन की निष्पक्षता पर उठते सवाल राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। पड़ोसी देशों से अवैध घुसपैठ, सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव और कानून-व्यवस्था की चुनौतियां भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं। इन मुद्दों पर ममता सरकार का रुख अक्सर रक्षात्मक दिखाई देता है, जबकि भाजपा इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर व्यापक समर्थन जुटाने का प्रयास करती है।

महाराष्ट्र के शहरी निकाय चुनावों और बिहार में भाजपा को मिली हालिया सफलता ने पार्टी के आत्मविश्वास को निश्चित रूप से बढ़ाया है। भाजपा का यह विश्वास कि बंगाल अब भी राजनीतिक परिवर्तन के लिए तैयार है, केवल चुनावी आंकड़ों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह इसे एक लंबी रणनीति का हिस्सा मानती है। किंतु बंगाल कोई साधारण राजनीतिक मैदान नहीं है। यहां की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक स्मृति किसी भी दल के लिए आसान नहीं रही है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत आज भी उनकी जमीनी पकड़ और भावनात्मक अपील है, जो उन्हें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अलग, एक क्षेत्रीय और स्थानीय नेता के रूप में स्थापित करती है। आने वाले विधानसभा चुनाव वास्तव में इस बात की कसौटी होंगे कि जनता विकास, स्थिरता और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देती है या फिर भावनात्मक और पहचान आधारित राजनीति को? क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटकर यह सिद्ध कर पाएंगी कि केंद्र से टकराव ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, या भाजपा जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल होगी कि परिवर्तन ही स्थायित्व और विकास का रास्ता है, यह प्रश्न अभी खुला हुआ है। अदालती प्रक्रियाएं, राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी रणनीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन अंतिम निर्णय बंगाल की जनता के हाथ में है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति आज संकीर्णता और सांप्रदायिक ध्रूवीकरण के ऐसे दौर से गुजर रही है, जिसने विकास की गति को गंभीर रूप से अवरुद्ध किया है। कभी देश की आर्थिक, औद्योगिक और बौद्धिक राजधानी कहलाने वाला बंगाल-विशेषकर कोलकाता, आज निवेश, उद्योग और रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। ममता बनर्जी के लंबे शासनकाल में औद्योगिक विश्वास का क्षरण, पूंजी पलायन, बंद होती इकाइयाँ और युवाओं का अन्य राज्यों की ओर पलायन इस गिरावट के स्पष्ट संकेत हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर उठते प्रश्न, विपक्षी आवाज़ों का दमन और चुनावी हिंसा की घटनाएँ राज्य के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर गहरी चोट करती हैं। इसके साथ ही, राज्य में सामाजिक ताने-बाने को लेकर बढ़ती आशंकाएँ भी कम चिंताजनक नहीं हैं। अनेक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक संबंधों को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं; विशेषकर हिंदू समाज के एक हिस्से में असुरक्षा की भावना ने जनमन को आहत किया है। इन घटनाओं और धारणाओं ने जनता के भरोसे को कमजोर किया है और शासन के प्रति निराशा को बढ़ाया है। राजनीति जब पहचान और विभाजन के इर्द-गिर्द सिमटती है, तो विकास, समावेशन और सामाजिक सौहार्द पीछे छूट जाते हैं, यही आज के बंगाल की त्रासदी बनती दिख रही है।

ऐसे समय में बंगाल की जनता के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग होना अनिवार्य है। यह राज्य केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि उसकी अस्मिता उसकी बौद्धिक परंपरा, भावनात्मक संवेदनशीलता, धार्मिक सहअस्तित्व, आध्यात्मिक खोज और समृद्ध साहित्यिक विरासत से निर्मित है-रवींद्रनाथ से विवेकानंद तक की धरोहर इसे दिशा देती रही है। दंगों, हिंसा और भय के साए में इस अस्मिता पर जो दाग लगे हैं, उन्हें मिटाने का मार्ग शांतिपूर्ण, जागरूक और निर्भीक लोकतांत्रिक सहभागिता से ही निकलेगा। आगामी चुनाव जनता के लिए आत्ममंथन और आत्मनिर्णय का अवसर हैं-जहाँ मत केवल सत्ता नहीं, बल्कि बंगाल के भविष्य, उसकी संस्कृति और उसके लोकतांत्रिक आत्मसम्मान की रक्षा का माध्यम बनना चाहिए। बंगाल की बनती नई तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह तस्वीर संघर्ष और संभावनाओं, आशंकाओं और उम्मीदों से बनी है। एक ओर सत्ता का अनुभव और जनाधार है, तो दूसरी ओर आक्रामक विपक्ष और राष्ट्रीय राजनीति की ताकत। लोकतंत्र की यही खूबी है कि वह अंतिम शब्द जनता को देता है। बंगाल के मतदाता ही तय करेंगे कि शह-मात की इस राजनीति में अगली चाल किसकी होगी और कौन-सा पक्ष अंततः बाजी मारेगा।

'सीमा मैडम 3 बार घर आईं, थाने में किया टॉर्चर...' बागपत के युवक ने महिला अफसर पर लगाए गंभीर आरोप

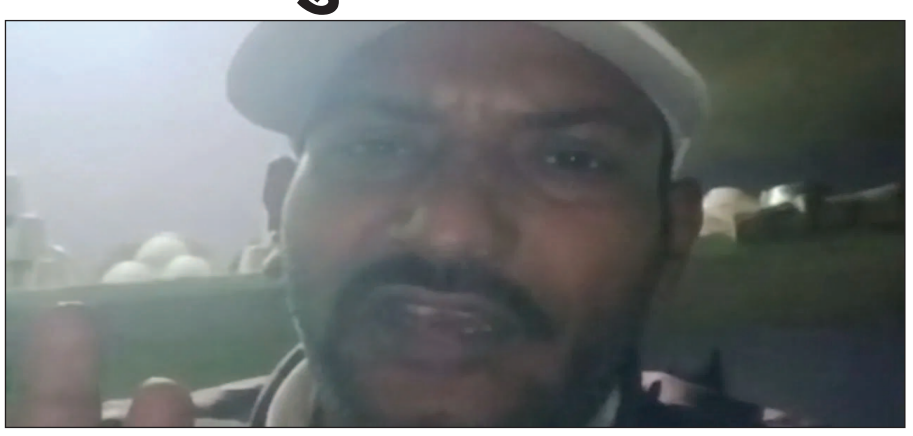

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत। यूपी के बागपत जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशश की, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। मेरठ में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। युवक ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है। घटना बागपत कोतवाली की है। युवक की पहचान फिरोज के रूप में की गई है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जहर खाने से पहले युवक ने वीडियो बनाया था। युवक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि पुलिस ने उसे बेवजह थाने बुलाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि एक मामले में निपटारा करने के नाम पर पुलिस उससे रिश्वत की मांग कर रही थी।

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उच्चाधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि किसी भी स्तर पर पुलिसकर्मियों की लापरवाही या गलत आचरण सामने आता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एएसपी बागपत प्रवीण चौहान ने बताया की वायरल वीडियो और पूरी घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा।

महिला दरोगा पर भी रिश्वत मांगने का आरोप

युवक ने महिला दरोगा सीमा समेत थाने के अन्य पुलिसकर्मियों पर पैसे के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो में युवक महिला थाने में मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। साथ ही वीडियो में युवक यह भी कर रहा है मेरे साथ की गई मारपीट की घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैट है, जिसका जांच की जा सकती है। जहरीला पदार्थ खाने के बाद फिरोज की हालत बिगड़ गई, जिसके तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालात अभी भी गंभी बनी हुई है।

संभल हिंसा : मास्टरमाइंड सारिक साठा की बढ़ी मुश्किलें, घर कुर्क करने पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम

आर्यावर्त संवाददाता

संभल। जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के मकान और अन्य चीजों की बुधवार को कुर्की शुरू हो गई। जिला न्यायालय से मंगलवार को आदेश जारी होने के बाद पुलिस-प्रशासन की टीम करीब 12 बजे शारिक साठा के 210 गज में बने पुश्तैनी मकान पहुंची।

यहां मुनादी कराते हुए साठा के हिस्से की एक चौथाई संपत्ति कुर्क करने का ऐलान किया। हिंसा के दौरान पथराव, फायरिंग और आगजनी में भीड़ में शामिल बिलाल, नईम, कैफ और अयान की गोली लगने से मौत हो गई थी। जांच में हिंसा भड़काने व हत्या की साजिश रचने में शारिक साठा का नाम सामने आया था। कोतवाली पुलिस ने शारिक साठा के खिलाफ चार लोगों की हत्या के मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। वह चारों मामलों में वांछित चल रहा है।

कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, दोस्तों से मिलकर आ रहे छात्रों की कार पेड़ से टकराई<, दो की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कल्याणपुर के आवास विकास तीन में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में दो छात्रों की मौत हुई है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

पनकी से कल्याणपुर की तरफ आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आवास विकास तीन के पास सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। आस पास के लोग दौड़े और कार सवार युवकों को सामने स्थित निजी अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों ने कन्नौज निवासी बी फार्मा के छात्र प्रथम पाण्डेय को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दिवंगत छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

गंभीर रूप से घायल कन्नौज के इंदरगढ़ निवासी आर्यन यादव, कन्नौज थानाक्षेत्र के पनियारी पुरवा

निवासी सत्यम पाल और कन्नौज के सौरिख निवासी आकाश यादव को सर्वोदय नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान आकाश यादव की भी मौत हो गई।

बताया जा रहा है दिवंगत छात्र मंधना के एक इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ाई करते थे। देर रात वह अपने पनकी स्थित एक कालेज के दोस्तों से मिलकर वापस अपने हॉस्टल जा रहे थे। हादसा पास में लगे सीसी कैमरे में कैद हुआ है। घटना में स्विफ्ट कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त कार किसी भाजपा के नगर अध्यक्ष की बताई जा रही है।

पुलिस ने स्वजन को घटना की सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम भेजा है।कल्याणपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। अन्य का इलाज जारी है।स्वजन को जानकारी दी गई है।

सभा में किसान नेता की पिटाई के बाद हुए फरार

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे किसान यूनियन के पंचायत के दौरान बुधवार को अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। किसी विवादित टिप्पणी को लेकर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ यादव और महिला सदस्यों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मामला हाथापाई में बदल गया। आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद नाराज महिलाओं ने उन पर लात-घूंसे और जूतों से हमला कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसमें महिलाएं भी आपस में भिड़ती दिखीं। स्थिति अनियंत्रित होता देख प्रदेश अध्यक्ष वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह महिलाओं को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया।हमलावर महिला शीला ने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि यूनियन के कार्यों में लूट-खसोट और मनमानी की भी शिकायतें लंबे समय से उठती रही हैं।

देहली बाजार में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा का शुभारंभ

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के देहली बाजार में बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि व ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक (अंचल कार्यालय लखनऊ) मृत्युंजय तथा मंडल प्रमुख (अयोध्या) अवधेश कुमार तिवारी के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि शिवकुमार सिंह ने कहा कि देहली बाजार में बैंक शाखा खुलने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं सहजता से उपलब्ध होंगी। इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और उपभोक्ताओं को अब बैंकिंग कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक कृष्ण दीपक वर्मा, उप प्रबंधक अनुज

कुमार, ग्राम प्रधान विपिन यादव, प्रधान प्रतिनिधि विक्रम प्रताप सिंह 'गोलू', अभय प्रताप सिंह अजमल खान, मो. जकी, अफरोज जमा पठान, ग्राम प्रधान शिव बहादुर (पीरो सरैया), विकास सिंह, करमजीत सिंह गोरे, इंद्र प्रताप सिंह (पूर्व उपनिरीक्षक), शेष नारायण श्रीवास्तव, शिव प्रताप सिंह (देवलपुर) सहित अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 30 से

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय आई क्यू ए सी व हिंदी विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 30 व 31 जनवरी को होगी। महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद संगोष्ठी कक्ष में होने वाली भारतीय भाषा परिवार अंतर्सम्बंध और सांस्कृतिक संवाद विषयक इस संगोष्ठी में देशभर के विद्वान अपने विचार व्यक्त करेंगे। संगोष्ठी के समन्वयक हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंद्रमणि कुमार ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन के औपनिवेशिक, यूरो केंद्रित और विभेदकारी दृष्टिकोण को चिन्हित करते हुए इस संदर्भ में वैकल्पिक दृष्टिकोण की प्रस्तावना तैयार करना है। इस दृष्टिकोण में भारत की विभिन्न भाषाओं में समानता, सहजीविता और सांस्कृतिक संवाद के सूत्रों का रेखांकन निहित है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन भारतीय भाषा समिति द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित दो पुस्तकों 'भारतीय भाषा परिवार अ न्यू फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक्स' और कलेक्ट स्टडीज ऑन भारतीय भाषा परिवार पर्सपेक्टिव एंड होरीज़ंस' और उनमें उठाए गए मुद्दों पर केंद्रित होगा। संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. रमेश चंद्र शर्मा, मुम्बई विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. रामजी तिवारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. अभिनव कुमार मिश्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रो. गजेंद्र पाठक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. विजय कुमार राय, रामजस कॉलेज दिल्ली के डॉ उमाशंकर पांडेय , युगतेवर के सम्पादक कमलनयन पांडेय व के एन आई के पूर्व प्राचार्य प्रो. राधेश्याम सिंह सहित अन्य जाने-माने विद्वान, शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी अपने विचार रखेंगे।

तीन दिन बाद बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के आसार, लौटेगी ठंड

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। । तेजी से बढ़ रहे तापमान पर जल्द लगाम लगेगी। तीन-चार दिन के लिए ठंड एक बार फिर लौटेगी। 23 जनवरी की शाम से पश्चिमोत्तर से बादल आएंगे। 24 जनवरी को गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की वजह बनेंगे।

पश्चिमोत्तर भारत में मौसम के इस बदलाव की वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव दो से तीन दिन में दिखेगा। जिले का अधिकतम व न्यूनतम तापमान गिरेगा। यह पूर्वानुमान है अध्ययन के आधार पर मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय का।

मौसम विज्ञानी ने बताया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की

गिरावट दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। 27 जनवरी तक मौसम के इस बदलाव का अवसर दिखेगा। उसके बाद फिर से तापमान तेजी से बढ़ेगा। उधर मंगलवार को तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा।

अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड हुआ। जनवरी के दूसरे पखवारे में तेजी से बढ़ते तापमान की वजह मौसम विज्ञानी बीते दिनों सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते एक सप्ताह में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, वह तिब्बत की ओर बढ़ने के क्रम में हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड तक आते-आते कमजोर हो गए। तिब्बत तक मजबूती से नहीं पहुंच सके।

इसके कारण समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूप का प्रभाव बढ़ा रहा और तापमान चढ़ता रहा। जनवरी के दूसरे सप्ताह में ठंड का प्रभाव कम होने का कारण मौसम विज्ञानी जलवायु परिवर्तन के कारण ठंड के मौसम का सिकुड़ना बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते कुछ वर्षों से ठंड का मौसम 90 दिन की जगह 75 से 80 दिन में सिमट जा रहा है। ऐसे में कभी ठंड की शुरुआत देर से हो रही, कभी समापन जल्दी हो जा रहा है।

नफीसा खातून को मिला भारतेंदु हरिश्चंद्र अन्तर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। हिंदी भाषा सेवा और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर पहचान बनाने वाली नफीसा खातून को "भारतेंदु हरिश्चंद्र अन्तर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2026" से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान हिंदी भाषा के संवर्धन, साहित्यिक योगदान और सामाजिक सक्रियता के लिए प्रदान किया गया।नफीसा खातून को जनपद सुल्तानपुर में भी अब तक कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाज़ा जा चुका है। उनके कार्यों को न केवल साहित्यिक जगत ने सराहा है, बल्कि जनपद के नागरिकों और संस्थाओं ने भी लगातार सम्मानित किया है।यदि नफीसा खातून के व्यक्तित्व और कार्यों की बात करें तो वे सामाजिक मुद्दों, महिलाओं के सशक्तिकरण और जनहित से जुड़े विषयों पर हमेशा मुखर रही हैं। वे एक निडर और स्पष्टवादी महिला के रूप में जानी जाती हैं, जो विभिन्न मंचों तथा अधिकारियों के समक्ष महिलाओं तथा समाज से जुड़ी चुनौतियों को बेझिझक उठाती हैं।नफीसा खातून सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं और स्थानीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। उनके कार्यों और योगदान ने उन्हें आज की युवा और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित किया है।उनकी यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि सुल्तानपुर जनपद का भी नाम रोशन करने वाली है।

एसएन मेडिकल कॉलेज की 200 करोड़ की बिल्डिंग में दरार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने गुणवत्ता पर उठे सवाल

डक्ट वाली जगह पर दरार आ गई थी। इसकी मरम्मत करा दी गई है। नई बिल्डिंग में जो भी कमी सामने आ रही है, उसे ठीक कराया जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, प्राचार्य, एसएन मेडिकल कालेज।

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज की 200 करोड़ रुपये से बनी आठ मंजिला सुपरस्पेशियलिटी बिल्डिंग में दरार आ गई है। बिल्डिंग में एक फीट तक गहरी दरार है। वर्ष 2019 में बनना शुरू हुई बिल्डिंग का 16 माह पहले ही लोकार्पण किया गया था।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने इसका वीडियो जारी करते हुए काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद एसएन मेडिकल कालेज प्रशासन ने मरम्मत कराई है।

इंटरनेट मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दरार में लोहे की छड़ को डालते हुए नजर आ रहे हैं। वह निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि यहां बड़े-बड़े अधिकारी आते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया है। वीडियो बनाने से सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहा है, लेकिन वह रुकते नहीं हैं। कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वीडियो जारी कर काम की गुणवत्ता पर उठाए सवाल

वह डीन को चुनौती देते हुए कहते हैं कि उनके विरुद्ध एफआईआर करानी है तो करा लें। उन्होंने निर्माण कार्य में इंजीनियरों व प्रशासन पर कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए कहा कि सभी ने कमीशन खाया है। गृह मंत्री अमित शाह समेत उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशान साधा है।

अमृत सरोवर योजना की खुली पोल, कागजों में 29 लाख खर्च, जमीन पर अधूरा तालाब

सुलतानपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गांवों में जल संरक्षण को लेकर शुरू की गई अमृत सरोवर योजना की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बल्दीराय विकास खंड की ग्राम पंचायत बरसांवां में स्थित शीतल बाबा अमृत सरोवर के निर्माण को लेकर लगाए गए सूचना बोर्ड ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं।अमृत सरोवर का निर्माण कार्य 5 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था, जिसकी कुल लागत करीब 28.96 लाख खर्च हुए हैं। इसमें श्रमांश मद में 18.46 लाख रुपये और सामग्री मद में 10.49 लाख रुपये खर्च होना बताया गया है। हालांकि मौके पर पहुंचने पर हालात इससे बिल्कुल उलट नजर आते हैं।गांव निवासी सुल्तान बेग ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि तालाब में न तो पर्याप्त खुदाई कराई गई और न ही जल संरक्षण के मानकों का पालन किया गया।

ग्रेटर नोएडा में डीसीपी ऑफिस के ऊपर बने बैरक में कांस्टेबल ने लगाई फांसी, ड्यूटी से लौटने के बाद क्यों उठाया ये कदम

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में 35 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली है। ये शख्स फायर डिपार्टमेंट में फायरमैन के तौर पर काम करता था। शख्स ने ड्यूटी से लौटने के बाद डीसीपी ऑफिस के ऊपर बने फायर विभाग के कार्यालय में बने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब एक फायर कर्मी ने उसे ड्यूटी पर आने के लिए करीब 5:30 बजे फोन किया, तो उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद फायरकर्मी कमरे में पहुंचा, जहां कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो दरवाजा तोड़कर देखा गया। अंदर फायरकर्मी पंखे से लटका हुआ मिला।

इसके बाद घटना की जानकारी फायर विभाग के अधिकारियों को दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और मृतक को फंदे से उतारकर शव का

पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

बैरक में मिला शव, कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान संदीप कुमार (35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बागपत जिले का रहने वाला था। वर्ष 2016 में वह फायर विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुआ था और हाल ही में ग्रेटर नोएडा में फायर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसके साथी कर्मियों ने बताया कि वह पढ़ाई में काफी अच्छा था और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, इसलिए अचानक आत्महत्या किए जाने की घटना पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बैरक से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

परिजनों को दी गई सूचना

थाना प्रभारी नॉलेज पार्क सर्वेश कुमार ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ ही, बैरक में साथ रहने वाले अन्य कर्मियों से भी पूछताछ की गई है।

अन्य कर्मियों का कहना है कि संदीप अलग कमरे में रहता था और रात में ड्यूटी से वापस लौटा था। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों को लेकर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, जिनमें ड्यूटी के दौरान मानसिक तनाव, पढ़ाई का दबाव या कोई अन्य कारण शामिल हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

एप्पल साइडर विनेगर से वजन घटाना कितना खतरनाक? एक्सपर्ट ने बताया सच

वीडियो या रील्स को देखकर एप्पल साइडर विनेगर से वजन घटाना चाहते हैं तो जान लें ये बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि ये आंतों तक को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप इसका ज्यादा यूज करते हैं। सीनियर डाइटिशियन गीतिका चोपड़ा ने वेट लॉस जर्नी में इसके होने वाले नुकसान बताए हैं। चलिए आपको बताते हैं।

वजन घटाने के लिए मार्केट में नए-नए तरीके आ गए हैं। बिना एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लिए लोग ऐसे कई तरीके आजमा रहे हैं जो उन्हें बीमार तक कर रहे हैं। वजन घटाना एक लंबा प्रोसेस है पर वीडियो और रील्स को देखकर लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें बीमार बना रही हैं। वेट लॉस जर्नी में डाइट का रोल अहम है। इस दौरान कई ऐसे ड्रिंक्स पिए जाते हैं तो फैट बर्नर के रूप में काम आते हैं। इनमें से एक एप्पल साइडर विनेगर भी है। सेब के सिरके को वजन घटाने के घरेलू नुस्खों में लंबे समय से शामिल किया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे ऐसे यूज करना सेफ नहीं है। लोग मानते हैं कि सेब के सिरके को पीने से तेजी से फैट बर्न होता है जबकि ऐसा नहीं है। अगर वजन घटा है तो ये स्टेबल नहीं होता। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी-कभी इस तरह का वेट लॉस बड़े नुकसान का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट से जानें क्यों एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस में खतरनाक साबित हो सकता है। सेब का रस निकालकर इस जूस की नेचुरल शुगर पर खमीर काम करता है। इस तरह ये अल्कोहल (एथेनॉल) में बदल जाता है। इसे एप्पल साइडर कहा जाता है। अब इस एप्पल साइडर को खुली हवा में रख दिया जाता है जहां इसमें मौजूद Acetobacter बैक्टीरिया इसे ऑक्सिडाइज करके एसिटिक एसिड में बदलता है। यही एसिड सिरके का मेन न्यूट्रिएंट होता है। थोडे. समय बाद ये पूरी तरह एप्पल साइडर विनेगर बन जाता है।

वेट लॉस में एप्पल साइडर विनेगर के नुकसान

सीनियर डाइटिशियन गीतिका चोपड़ा कहती हैं कि आजकल एप्पल साइडर विनेगर (एसीवी) को सोशल मीडिया पर फास्ट वेट लॉस ड्रिंक के रूप में प्रोमोट किया जा रहा है। पर साइंस कहती है कि ये अप्रोच न सिर्फ गुमराह करती है बल्कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक भी हो सकता है। एसीवी में एसिटिक एसिड होता है जो भूख को सरपास कर सकता है। इस वजह से ब्लड शुगर को थोड़ा कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन फैट बर्निंग या रैपिड वेट लॉस का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि जो लोग एसीवी से जल्दी वेट कम होने का बेनिफिट फील करते हैं, वो अक्सर फैट लॉस नहीं बल्कि वाटर लॉस होता है। ये कुछ समय ही रहता है और बॉडी को कई नुकसान तक झेलने पड़ जाते हैं।

ज्यादा एप्पल साइडर विनेगर के नुकसान

गीतिका चोपड़ा जी कहती हैं कि अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में रोज खाली पेट पीते हैं तो इससे पेट की लाइनिंग डैमेज होती है। इसके अलावा एसिडिटी, गैसट्रिक, गले में खरास और दांतों के इनेमल कम होने जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। लॉन्ग टर्म लॉस को देखें तो इससे पोटेशियम लेवल गिर सकता है जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, थकान या दिल को नुकसान जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। एक्सपर्ट ने बताया कि डायबिटीज है तो इसका यूज बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। किडनी की बीमारी होने पर ऐसे लोग एसीवी को न पिएं क्योंकि इससे रेनल स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए एसीवी को नेचुरल और सेफ मानना एक बड़ा मिथ है।

हेल्दी वेट लॉस कैसे होता है

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक हेल्दी वेट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एप्पल साइडर विनेगर मेटाबॉलिज्म का जादुई सॉल्यूशन नहीं है। सेफ फैट लॉस सिर्फ बैलेंस डाइट, प्रोटीन, फाइबर इंटेक, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल से ही संभव है। एसीवी अगर लेना भी है तो इसे डिल्यूएटिड फॉर्म, खाने के बाद और कभी-कभी लेना चाहिए। इसे वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि डाइजेशन सपोर्ट के लिए इस्तेमाल में लेना चाहिए। एक्सपर्ट ने कहा कि फास्ट वेट लॉस के नाम पर बॉडी को एसिड से स्ट्रेन देना हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।

गंदे सफेद जूते मिनटों में होंगे नए जैसे... धोने की नहीं पड़ेगी जरूरत, ये हैक अपनाएं

सफेद रंग जहां देखने में बहुत अच्छा लगता है तो वहीं ये गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। खासतौर पर जूते तो धूल–मिट्टी के संपर्क में सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आपको भी वाइट शूज पहनने का शौक है तो जान लें कि इसे बिना धोए आप कैसे क्लीन कर सकते हैं।

सफेद रंग के कपड़ों से लेकर फुटवियर तक काफी पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर स्किन टोन के लिए परफेक्ट होता है। कुछ लोगों को तो मोस्टली टाइम वाइट अटायर या फिर फुटवियर पसंद आते हैं। ये रंग देखने में जितना अच्छा लगता है, इसकी बनी चीजों की देखभाल भी करना उतना ही सावधानी वाला काम होता है, क्योंकि जरा सा भी दाग सफेद रंग पर बिल्कुल साफ दिखाई देता है जो बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। वाइट स्नीकर्स पहनने का शौक है, लेकिन ये जल्दी गंदे हो जाते हैं तो यहां दिए गया हैक आपके काफी काम आ सकता है। इससे आपको जूते धोने भई नहीं पड़ेंगे और फटाफट साफ भी हो जाएंगे।

सफेद रंग के जूते एक से दो बार में ही गंदे दिखाई देने लगते हैं। इनको धो दिया जाए तो सूखने में भी थोड़ा टाइम जाता है। सर्दियों मे तो कपड़े ही सुखाना मुश्किल हो जाता है ऐसे में आप बार-बार शूज को नहीं धो सकते हैं। बार-बार धोने से ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं और पुराने दिखने लगते हैं। अगर आपके सफेद जूते गंदे हो गए हैं तो जान लें कि कौन सा सिंपल हैक अपनाकर आप इसे साफ कर सकते हैं।

क्या चाहिए चीजें?

सफेद जूते साफ करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए वो ज्यादातर आपके घर में ही मिल जाएंगी। इससे न सिर्फ जूते साफ हो जाएंगे, बल्कि खोई चमक भी वापस आएगी। आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा (ध्यान रखें कि बेकिंग पाउडर नहीं लेना है), नॉर्मल वाला वाइट टूथपेस्ट लें। आपको चाहिए होगा कोई पुराना टूथब्रश या फिर सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला कोई भी ब्रश। इसके अलावा एक कप पानी और लिक्विड डिटर्जेंट या फिर हल्का साबुन जो ज्यादा हार्श न हो। अब जान लें कि कैसे करें जूतों को साफ।

बिना धोए साफ करें जूते

आपको सबसे पहले सूखे ब्रश से जूतों को अच्छी तरह से झाड़ लेना है ताकि जो भी धूल-मिट्टी जमी हुई है वो हट जाए। खासतौर पर जो डिटेलिंग वाले किनारे हैं उनको सही से साफ करें।

इसके बाद एक बाउल में बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट या फिर लिक्विड सोप लेकर अच्छी तरह से मिला लें। ये एक गाढ़ा पेस्ट बन जाना चाहिए। इसके लिए आप सारी चीजों को बराबर मात्रा में ले सकते हैं।

अब आपको ये पेस्ट अपने जूतों पर अप्लाई कर देना है। दाग-धब्बे वाली जगह पर थोड़ा ज्यादा पेस्ट लगाएं। इसके बाद कोई खराब टूथब्रश लेकर सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए जूतों को क्लीन कर लें।

ये पेस्ट आपको जूतों पर लगा हुआ छोड़ देना है। कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के लिए लगे रहने दें। इससे ये हल्का सूख जाएगा।

इसके बाद आपको एक सूती कपड़ा पानी में भिगोकर निचोड़ लेना है और फिर इससे अपने जूतों को साफ कर लें। इस तरह से बिना धोए आपके जूते साफ हो जाएंगे।

साफ किए गए जूतों को या तो कुछ देर के लिए आप धूप में रख दें या फिर हेयर ड्रायर से आप क्लीन कर सकते हैं और ब्लोअर के सामने रख सकते हैं।

जूतों से जुड़े हाइजीन रखें ध्यान

जूते न सिर्फ बाहर से गंदे होते हैं, बल्कि इनमें अंदर भी बैक्टीरिया पनप जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इससे जुड़े हाइजीन का ध्यान रखें। जैसे आप कम से कम 15 दिन में एक बार तो जूते जरूर धोएं। इसके अलावा जूतों के अंदर कीटाणुनाशक स्प्रे आप दो-तीन दिन के अंदर करते रहें। इससे बदबू भी दूर होती है। आप जूतों की बदबू हटाने के लिए बेकिंग सोडा इसके अंदर छिड़ककर रख सकते हैं और फिर धूप दिखाएं। डेली रूटीन में साफ मोजे पहनें। इससे आपके पैर फंगल इंफेक्शन से बचे रहेंगे। जूते पहनने से पहले अपने पैरों को धोकर अच्छी तरह से सुखाना चाहिए।

सर्दियों में मैट लिपस्टिक लगाने पर भी नहीं फटेंगे होंठ, बस अपना लें ये 5 टिप्स

सर्दियों में सभी होंठों के सूखने से परेशान रहते हैं। ऐसे में मैट लिपस्टिक लगाना किसी बुरे सपने जैसा लगने लगता है। मैट लिपस्टिक पहले से ही कम चिकनी होती है और ठंडी हवाएं उसे और शुष्क बना देती हैं। इसे लगाने के बाद होंठ बुरी तरह फटने लगते हैं और पूरा लुक बिगड़ जाता है। ऐसे में ये मेकअप टिप्स आपके काम आ सकती हैं, जिनकी मदद से सर्दी में भी आप बेफिक्र हो कर मैट लिपस्टिक लगा पाएंगी।

होंठों को एक्सफोलिएट करें

अगर आप शुष्क होंठों पर ही मैट लिपस्टिक लगा लेंगी तो वे और फटे दिखाई देंगे। ऐसे में पहले होंठों की देखभाल के तौर पर उन्हें एक्सफोलिएट करें। इससे मृत त्वचा हट जाएगी और लिपस्टिक के लिए मुलायम बेस मिलेगा। आप चीनी में शहद या नारियल तेल मिलाकर होंठों पर घिस सकती हैं। यह एक प्राकृतिक स्क्रब की तरह काम करेगा। हालांकि, अगर आपके होंठों से खून आ रहा हो तो स्क्रब करने की गलती न करें।

लिप बाम लगाने के बाद कुछ देर इंतजार करें

लिप बाम होंठों को हाइड्रेट करने वाला उत्पाद है, जो सर्दियों में सभी के पास होता ही है। हालांकि, कई महिलाएं इसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद लिपस्टिक लगा लेती हैं। ऐसा करने के बजाय लिप बाम लगाने के बाद 10 मिनट रुकें और फिर लिपस्टिक लगाएं। लिपस्टिक इस्तेमाल करने के तुरंत पहले टिश्यू पेपर से अतिरिक्त लिप बाम साफ कर लें। इससे होंठों में नमी बनी रहेगी और लिपस्टिक ज्यादा देर तक टिकी रहेगी।

लिप प्राइमर लगाएं

मैट लिपस्टिक लगाने से पहले आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला लिप प्राइमर भी लगाना चाहिए। यह होंठों और लिपस्टिक के बीच एक सुरक्षात्मक परत की तरह काम करेगा। यह परत नमी को होंठों में रोककर रखेगी, जिससे उनका फटना भी कम हो जाएगा। आपको शिया बटर और नारियल तेल जैसी सामग्रियों वाला लिप प्राइमर लगाना चाहिए, जो होंठों को नमी देने के साथ-साथ मुलायम भी बना देगा। इससे मैट लिपस्टिक होंठों की दरारों में भी नहीं भरेगी।

अच्छी मैट लिपस्टिक चुनें

अगर आप सस्ती या लोकल ब्रांड की मैट लिपस्टिक लगाएंगी तो आपके होंठों का फटना तय है। परेशानी से बचने के लिए जाने-माने ब्रांड वाली मैट लिपस्टिक ही इस्तेमाल करें और उसके फार्मूला पर ध्यान दें। विटामिन-ई जैसे तत्वों से लैस क्रीमी मैट लिपस्टिक सर्दियों के लिए सबसे अच्छी रहती हैं। इस मौसम में आपको लिक्विड मैट लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वे होंठों को ज्यादा शुष्क बना देती हैं।

लिप मास्क इस्तेमाल करें

केवल लिपस्टिक लगाने से पहले ही नहीं, बल्कि रोजाना होंठों की देखभाल करने की आदत डालें। इससे आपके होंठों का फटना कम हो जाएगा और वे हमेशा मुलायम बने रहेंगे। रात को सोने से पहले एक हाइड्रेटिंग लिप मास्क या पेट्रोलियम जेली लगा लें। आप इनकी जगह पर लिप बाम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हफ्ते में एक बार होंठों को एक्सफोलिएट करें और उन्हें नोचने की गलती बिलकुल न करें।

बाजार की पाठशाला: आईपीओ में जीएमपी क्या होता है, रजिस्ट्रार और बुक रनिंग लीड मैनेजर का क्या काम होता है, आसान भाषा में समझें

आईपीओ में जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) एक अनौपचारिक संकेत होता है, जो यह बताता है कि किसी कंपनी के शेयर लिस्टिंग से पहले अनलिस्टेड यानी ग्रे मार्केट में कितने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

मुंबई, एजेंसी। शेयर बाजार में अधिकतर निवेशक कम समय में मोटा मुनाफा कमाने के लिए अक्सर आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) का रुख करते हैं। लेकिन, आईपीओ में निवेश करने से पहले इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिनके बारे में निवेशकों को जानना बेहद जरूरी होता है। इनमें सबसे आम सवाल जिसको लेकर अक्सर निवेशकों के मन में संशय रहता है, वह है जीएमपी क्या होता है, रजिस्ट्रार की भूमिका क्या है और बुक रनिंग लीड मैनेजर आखिर क्या करता है। सही जानकारी के बिना आईपीओ में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है।

आईपीओ में जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) एक अनौपचारिक संकेत होता है, जो यह बताता है कि किसी कंपनी के शेयर लिस्टिंग से पहले अनलिस्टेड यानी ग्रे मार्केट में कितने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए किसी आईपीओ का इश्यू प्राइस 100 रुपए है और उसका जीएमपी 40 रुपए चल रहा है, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि शेयर की लिस्टिंग करीब 140 रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि यह सिर्फ बाजार की धारणा पर आधारित होता है, इसे न तो सेबी नियंत्रित करता है और न ही इसकी कोई गारंटी होती है। कई बार अच्छा जीएमपी होने के बावजूद शेयर कमजोर लिस्ट होते हैं और कभी-कभी बिना जीएमपी के भी शानदार लिस्टिंग देखने को मिलती है।

वहीं, रजिस्ट्रार वह संस्था होती है जो आईपीओ से जुड़े प्रशासनिक और ऑपरेशनल कार्यों को संभालती है। इसमें निवेशकों से मिले आवेदन, शेयरों का आवंटन (अलॉटमेंट), रिफंड की प्रक्रिया और डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करना शामिल होता है। आसान शब्दों में कहें तो रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करता है कि किस निवेशक को कितने शेयर मिले और पैसा सही तरीके से एडजस्ट हो। सरल शब्दों में कहें तो रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करता है कि शेयर आवंटन की प्रक्रिया निष्पक्ष, सटीक और समय पर पूरी हो। भारत में लिंक इनटाइम, केफिन टेक्नोलॉजीज और एमयूएफजी इंटाइम जैसी कंपनियां प्रमुख रजिस्ट्रार हैं।

अब बात करते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) की। यह आईपीओ की पूरी योजना और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है। यह आमतौर पर बड़ी निवेश बैंक या ब्रोकरेज फर्म होती हैं, जो कंपनी को यह तय करने में मदद करती हैं कि आईपीओ का साइज कितना हो, प्राइस बैंड क्या रखा जाए और निवेशकों से कितनी मांग आ सकती है। बीआरएलएम ही संस्थागत निवेशकों से बातचीत करता है और पूरे इश्यू को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स जैसी संस्थाएं अक्सर इस भूमिका में दिखती हैं।

इसके अलावा, बुक रनिंग लीड मैनेजर आईपीओ की मार्केटिंग करता है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो आयोजित करता है और अंडरराइटर्स, रजिस्ट्रार तथा अन्य मध्यस्थों के साथ समन्वय बनाकर काम करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरी हो।

बाजार के जानकारों के अनुसार, आईपीओ प्रक्रिया में रजिस्ट्रार और बुक रनिंग लीड मैनेजर, दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग लेकिन एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और इनके सही तालमेल से ही कोई आईपीओ सफल बन पाता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में निवेश करना सही रणनीति नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, मुनाफे का रिकॉर्ड, कर्ज की स्थिति, भविष्य की योजनाएं और रिस्क फैक्टर भी उतने ही अहम होते हैं। आईपीओ के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिसे सेबी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज की साइट्स पर उपलब्ध कराया जाता है।

अगर भरोसेमंद और आधिकारिक स्रोतों की बात करें तो सेबी, एनएसई और बीएसई की वेबसाइट पर आईपीओ से जुड़ी सारी प्रमाणिक जानकारी मिलती है। समझदारी इसी में है कि निवेशक अफवाहों या ग्रे मार्केट के भरोसे नहीं, बल्कि ठोस जानकारी और अपनी जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर ही आईपीओ में निवेश करें।

बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल, बनाया एक और नया रिकॉर्ड

मुंबई, एजेंसी। बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच सोने और चांदी ने मंगलवार के कारोबारी सत्र में एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। एमसीएक्स पर कीमती धातुओं की कीमतें पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। गोल्ड फरवरी वायदा 1,47,996 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं सिल्वर मार्च वायदा 3,19,949 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना जहां रिकॉर्ड 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, तो वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी 3,01,315 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सिल्वर की कीमत 94.320 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। तो वहीं गोल्ड 4,708.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इससे पहले के सत्र में सोने ने 4,689.39 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड स्तर छुआ था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड से जुड़े बयानों और टैरिफ की धमकियों से वैश्विक तनाव बढ़ गया है, जिससे निवेशकों ने सुरक्षित निवेश यानी सेफ-हेवन विकल्पों की ओर रुख किया। खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 1.55 प्रतिशत यानी 2,255 रुपए की तेजी के साथ 1,47,894 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि मार्च डिलीवरी वाली चांदी 7,279 रुपए यानी 2.35 प्रतिशत की उछाल के साथ 3,17,554 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी।

यह तेजी उस समय आई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड मुद्दे का विरोध करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया।

कीमती धातुओं में यह उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड मुद्दे का विरोध करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी के बाद आई।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दोहराया कि यूरोपीय देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की धमकी पर वे अमल करेंगे।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि वे यूरोपीय संघ के 'एंटी-कोएरशन' तंत्र को लागू करने की मांग करेंगे। वहीं, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संयम बरतने की अपील की। इसके अलावा, डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के फैसले से भू-राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ गई है।

बाजार इस बात पर भी नजर रखे हुए हैं कि कहीं ट्रंप प्रशासन अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठाएगा। इससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंता बढ़ी है, जिसका फायदा भी कीमती धातुओं को मिल रहा है। इसके साथ ही, अमेरिका में आगे और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी सोने और चांदी की कीमतों को सहारा दे रही हैं। साल 2025 में भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से इन धातुओं को काफी सपोर्ट मिला था।

विशेषज्ञों के अनुसार, कीमती धातुओं में आई यह तेजी सुरक्षित निवेश के साथ-साथ चांदी की औद्योगिक मांग को भी दिखाती है। चांदी का उपयोग सोलर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है। विश्लेषकों ने कहा कि तकनीकी रूप से कॉमेक्स पर चांदी का रुख अभी मजबूत बना हुआ है। 85 से 88 डॉलर प्रति औंस का स्तर आने वाले समय में कीमतों को सहारा दे सकता है।

ऑगमोंट की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनाफावसूली के कारण कीमतों में थोड़ी गिरावट आ सकती है और चांदी 84 डॉलर प्रति औंस या 2,60,000 रुपए प्रति किलो तक आ सकती है, इसके बाद फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बहुत तेज बढ़त के बाद निवेशक मुनाफावसूली कर सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि आपूर्ति की चिंताओं और औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण लंबे समय में सोने और चांदी का रुझान मजबूत बना रहेगा।

शिंजो आबे को गोली मारने वाले अपराधी को आजीवन कारावास, जापान की अदालत ने सुनाई सजा

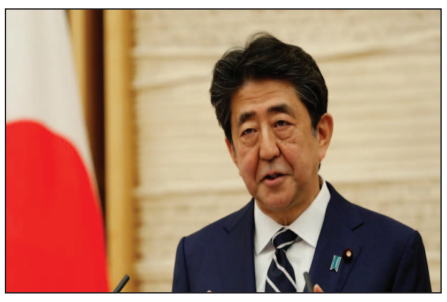

टोक्यो, एजेंसी। जापान की अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शिंजो आबे की हत्या करने की बात इस शख्स ने कबूल की थी। इस मामले ने जापान की सत्तारूढ़ पार्टी और एक विवादास्पद दक्षिण कोरियाई चर्च के बीच दशकों पुराने घनिष्ठ संबंधों को उजागर किया है।

जापान के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में शामिल शिंजो आबे प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद एक नियमित सांसद के रूप में कार्यरत थे। इसी दौरान 2022 में पश्चिमी शहर नारा में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने सख्त बंदूक नियंत्रण वाले देश को स्तब्ध कर दिया।

चर्च से पूर्व पीएम की हत्या का क्या कनेक्शन?

45 वर्षीय तेत्सुया यामागामी ने अक्टूबर में शुरू हुए मुकदमे में हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा का एलान किया। शूटर ने कहा कि वह एक विवादास्पद चर्च के प्रति नफरत से प्रेरित था। यामागामी ने कहा कि उसने आबे की हत्या तब की जब उसने पूर्व नेता की ओर से यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े एक समूह को भेजा गया एक वीडियो संदेश देखा। उसने आगे कहा कि उसका उद्देश्य उस चर्च को नुकसान पहुंचाना था, जिससे वह नफरत करता था और आबे के साथ उसके संबंधों को उजागर करना था।

सत्ताधारी पार्टी और चर्च के गहरे रिश्ते

अभियोजकों ने यामागामी के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी। वहीं, उनके वकीलों ने चर्च के अनुयायी के बच्चे के रूप में उनकी परेशानियों का हवाला देते हुए 20 साल से अधिक की सजा न देने की मांग की थी। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और चर्च के बीच घनिष्ठ संबंधों के खुलासे के बाद पार्टी ने चर्च से दूरी बना ली। इसके चलते जांच शुरू हुई, जिसकी वजह से चर्च की जापानी शाखा का कर-मुक्त धार्मिक दर्जा खत्म कर दिया गया और उसे भंग करने का आदेश दिया गया।

ट्रंप की अजीबो-गरीब हरकत, मीडिया को दिखाए कामयाबी के दस्तावेज फिर खुद उसे फर्श पर पटक दिया

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का मगंलवार को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सरकार के एक साल की उपलब्धियों का दस्तावेज दिखाया। हैरानी की बात ये रही कि उन्होंने मीडिया को दस्तावेज दिखाने के बाद खुद ही उसे जमीन पर पटक दिया। ट्रंप ने करीब दो घंटे तक मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान समेत आठ युद्ध रुकवाने के दावे को दोहराया। ट्रंप ने फिर से नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के फैसलों से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी।

ट्रंप ने गिनाईं ये उपलब्धियां

ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। मंगलवार को उनके कार्यकाल को एक साल पूरा हो गया। इस दौरान ट्रंप ने दावोस में आयोजित हो रहे वैश्विक आर्थिक सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने एक साल के कार्यकाल में अपनी सरकार द्वारा हासिल कथित उपलब्धियों का जिक्र किया।

इसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के अमेरिका में आने पर रोक और अमेरिका से करीब 26 लाख अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने का जिक्र किया।

ट्रंप ने अमेरिका में सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए व्यवसायिक ट्रक ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य करने

एच-1बी वीजा आवेदन की फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने आदि कथित उपलब्धियों का जिक्र किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कामयाबी के दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि पहले किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की है और इसके बाद बंडल को जमीन पर पटक दिया।

इसके बाद ट्रंप ने मिनेसोटा से गिरफ्तार किए गए अवैध अप्रवासियों की तस्वीरें भी दिखाईं। तस्वीरें दिखाने के बाद ट्रंप ने उन्हें भी जमीन पर पटक दिया।

अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो रहा, टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा, कनाडा के पीएम का बड़ा बयान

दावोस, एजेंसी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने दावोस में कहा कि दुनिया की मौजूदा व्यवस्था संकट में है और अमेरिकी वर्चस्व खत्म हो रहा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दिए अपने बयान में कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देते हुए ग्रीनलैंड मुद्दे पर डेनमार्क का समर्थन किया। हालांकि कनाडा के पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी टिप्पणियों में अमेरिका पर जमकर निशाना साधा।

मार्क कार्नी ने कहा, 'ताकतवर देश उन्हें माना जाता है, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट है जैसे चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इन देशों का दुनिया पर आर्थिक और सैन्य दबदबा है।' 'मध्य ताकत वाले देश जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया और ब्राजील का भी दुनिया की राजनीति में बड़ा असर रखते हैं।'

कार्नी ने कहा कि दुनिया की मौजूदा व्यवस्था बदलाव के दौर से नहीं गुजर रही है, बल्कि पूरी व्यवस्था ही संकट में है। ऐसे में मध्य ताकत वाले देशों को एकजुट होना चाहिए। कार्नी ने कहा 'अगर हम बातचीत की मेज पर नहीं आएंगे तो जल्द ही हमें बड़ी ताकतें खा जाएंगी।'

अमेरिका-कनाडा के संबंध खराब दौर में

गौरतलब है कि अमेरिका और कनाडा के संबंध भी इन दिनों अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही है। साथ ही कनाडा से होने वाले आयात पर भारी टैरिफ लगा दिया है। इसके चलते कनाडा, जो पारंपरिक तौर पर अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है, वहां राष्ट्रवाद का उदय और अमेरिका के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। बीते दिनों कनाडा के पीएम ने चीन का दौरा किया था, जिसे भी कनाडा द्वारा अमेरिका से दूरी और चीन से नजदीकी बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है।

ग्रीनलैंड पर यूरोप से भिड़े ट्रंप

वैश्विक व्यवस्था की बात करें तो ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगा दिए हैं और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप पर भी टैरिफ लगाने की बात कही है। इसे लेकर यूरोप में नाराजगी है और यूरोपीय देशों ने अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर चेताया है। फ्रांस ने तो साफ कह दिया है कि यूरोप की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी की है। अब कनाडा ने भी ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के समर्थन की बात कह दी है। यही वजह है कि नाटो के कमजोर होने की आशंका जाहिर की जा रही है।

'डोनाल्ड ट्रंप... भाड़ में जाओ', ग्रीनलैंड पर अमेरिकी आक्रामकता पर भड़के डेनमार्क के सांसद

कोपेनहेगन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच डेनमार्क के एक सांसद का बयान सुर्खियों में आ गया है। अपने बयान में सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड से दूर रहने की सलाह दी है। यूरोपीय संसद के सदस्य एंडर्स विस्टिसन ने ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड बिकने वाला नहीं है, इसलिए भाड़ में जाओ।

डेनमार्क के सांसद एंडर्स विस्टिसन ने यूरोपीय संघ की विधायिका में एक बहस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नाराजगी जाहिर की। वीडियो में देखा जा सकता है कि 38 वर्षीय विस्टिसन, ट्रंप की ओर से आर्कटिक क्षेत्र को हासिल करने की कोशिशों के बीच ग्रीनलैंड में अमेरिकी हितों पर केंद्रित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे।

डेनमार्क के सांसद ने क्या कहा?

सांसद एंडर्स विस्टिसन ने कहा, 'प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, कृपया ध्यान से सुनें। ग्रीनलैंड 800 वर्षों से डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा रहा है। यह एक एकीकृत देश है। यह बिक्री के लिए नहीं है।' इसके बाद विस्टिसन ने कहा, 'मैं इसे उन शब्दों में कहता हूं जिन्हें आप शायद समझ सकें: राष्ट्रपति महोदय, भाड़ में जाइए।'

इसके बाद उन्होंने डेनिश भाषा में अपना भाषण जारी रखा, लेकिन जल्द ही संसद के उपाध्यक्ष निकोले स्टेफानुटा ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सांसद की भाषा के लिए उन्हें फटकार लगाई और नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी।

लगी कड़ी फटकार

स्टेफानुटा ने उनसे कहा, 'साथी सांसद मुझे खेद है, यह हमारे नियमों के खिलाफ है।' उन्होंने आगे कहा, 'इस कमरे में अपशब्दों और अनुचित भाषा के इस्तेमाल को लेकर हमारे स्पष्ट नियम हैं। मुझे आपको बीच में टोकने के लिए खेद है। यह अस्वीकार्य है, भले ही इस विषय पर आपकी राजनीतिक भावनाएं कितनी भी प्रबल क्यों न हों।' गौरतलब है कि फटकार पड़ने के बाद डेनिश सांसद विस्टिसन ने अपने भाषण का मुद्दा ट्रंप से हटा दिया।

अधिकारियों को धमकी, लोगों को डराया जा रहा... ईसी ने सीएम ममता पर बोला

कोलकाता, एजेंसी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। चुनाव आयोग ने कहा कि ममता ने भड़काऊ भाषणों और गलत जानकारी से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया है। राज्य में ECI अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों का माहौल है, जिससे निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामे में कहा कि ममता ने एसआईआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए हैं। उन्होंने डर फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रामक व गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाई है।

आयोग ने कहा कि अन्य राज्यों के विपरीत पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक धमकियां और बाधाएं हैं। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा

कि लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया के प्रति गलत जानकारी देकर भड़काया जा रहा है। हलफनामे में कहा गया कि राज्य में ईसीआई अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों का माहौल है।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या- क्या कहा?

चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, उसमें कहा है कि ममता बनर्जी ने बयानों से लोगों को भड़काया है। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को निशाना बनाया है। जिसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आयोग ने कहा कि सीएम के बयानों के कारण निचले स्तर पर बीएलओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही कई तरह के हमले भी हुए हैं।

बंगाल की पुलिस व्यवस्था पर आयोग ने उठाए सवाल

आयोग ने कहा कि इस तरह के बयानों के कारण हमारे साथ काम करने वाले अधिकारियों में डर था। यही वजह है कि अधिकारियों ने मिलकर इस्तीफा पेश किया था। उन्होंने बताया था कि सुरक्षा के कारण वह इस्तीफा दे रहे हैं।आयोग ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस बीएलओ की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। यही वजह है कि आयोग ने बंगाल की पुलिस व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं।

डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी करने वालों पर बस्तर पुलिस की सख्त नजर

जगदलपुर। शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा, नामी-गिरामी कंपनियों की फ्रेंचाइजी, बीमा रिन्यूअल के नाम पर अतिरिक्त लाभ या फिर एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने जैसे तरीकों से साइबर ठग लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। बस्तर संभाग में ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अब साइबर अपराधियों ने अपना फोकस खास तौर पर ओल्ड एज यानी बुजुर्गों पर केंद्रित कर लिया है। वे लोग जो घर में अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं या तकनीकी जानकारी सीमित है, उन्हें आसानी से टारगेट किया जा रहा है। बीमा पॉलिसी के लाप्स होने या नए फायदे दिलाने के नाम पर बड़ी रकम ठगी जा रही है।

साइबर ठग पहले विश्वास जीतने के लिए छोटी रकम का मुनाफा दिखाते हैं। शेयर ट्रेडिंग या निवेश के नाम पर शुरुआत में कुछ पैसा वापस भी कर देते हैं, जिससे सामने वाला लालच में आ जाता है। इसके बाद बड़ी रकम इनवेस्ट करवाकर संपर्क तोड़ दिया जाता है। लालच और जल्दबाजी ही सबसे बड़ा हथियार बन रही है, जिसके चलते लोग समय रहते ठगी को समझ नहीं पाते।

2025 में हुए साइबर क्राइम के आंकड़े

बस्तर में साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए एसपी शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में आठ सदस्यीय स्पेशल साइबर टीम गठित की गई है।

इस टीम की अगुवाई डीएसपी गीतिका साहू कर रही हैं। टीम में इंस्पेक्टर गौरव तिवारी, दिलबाग सिंह, सब इंस्पेक्टर अमित सिदार, प्रमोद ठाकुर, निलांबर नाग सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।

वर्ष 2025 में फाइनेंशियल आईटी एक्ट एवं अन्य आईटी एक्ट के तहत 15 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

अलग-अलग राज्यों से जुड़े 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

80 लाख 64 हजार 755 रुपये की रकम साइबर ठगों के खातों में जाने से पहले रोकी गई है और कई खातों को होल्ड कराया गया।

जागरूकता अभियान से साइबर अपराध पर प्रहार

राष्ट्रीय न्यूज सर्विस के बस्तर रीजनल हेड केशव सल्होत्रा से चर्चा के दौरान एसपी बस्तर शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि साइबर क्राइम के पीछे सबसे बड़ी वजह लोगों में जागरूकता की कमी है। इसी को देखते हुए जिले भर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

स्कूल, कॉलेज, साप्ताहिक बाजारों और मोहल्लों में जाकर लोगों को साइबर ठगी के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। विशेष रूप से बुजुर्गों के घर-घर जाकर उन्हें कॉल, लिंक और ओटीपी से जुड़े खतरों के बारे में समझाया जा रहा है।

इसके साथ ही बड़े आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साइबर टीम के जवानों को सिविल ड्रेस में तैनात किया जा रहा है ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके।

एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन यूनिट के तहत देशभर की पुलिस एजेंसियां आपस में जुड़कर काम कर रही हैं। फर्जी सिम कार्ड और म्यूल अकाउंट संचालकों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।

खास रहा मानुषी छिल्लर के साथ साल 2016, ताजा की 10 साल पुरानी यादें

साल 2026 के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर दस साल पुरानी फोटो और यादों को शेयर करने का ट्रेंड चल रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स 2016 की खट्टी-मीठी यादों को शेयर कर रहे हैं। अब फेमिना मिस इंडिया और फिर मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर ने साल 2016 की यादों से पर्दा उठाया है और कई मजेदार यादों को शेयर किया है। मानुषी छिल्लर ने इंस्टाग्राम पर पुरानी मॉडलिंग की तस्वीरें और एमबीबीएस की छात्रा के रूप में कुछ फोटोज पोस्ट की हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक साल मैंने हैना मोंटाना की तरह कॉलेज और एम्स, नई दिल्ली में मिस इंडिया द्वारा चुने जाने के बाद अपने शुरुआती फोटोशूट के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की।

क्लास के बाद एंट्री फॉर्म के लिए अपनी पहली कुछ तस्वीरें क्लिक कीं, फिर अपना पहला कैंपेन बुक किया और फिर बाकी के कैंपेन मिलते चले गए।

उन्होंने लिखा, एहसास हुआ कि बायोकेमिस्ट्री मेरे जीन में नहीं है, लेकिन बाकी सब है। मेरी पहली क्लिनिकल पोस्टिंग जनरल सर्जरी के दौरान कोई बेहोश हो गया था, लेकिन मैं वो नहीं थी। फिर मिस इंडिया के लिए एक बार के लिए इंस्टाग्राम जॉइन किया, और आज एक दशक बाद हम यहां हैं।

अभिनेत्री के कैप्शन से साफ है कि वाकई उन्होंने प्रसिद्ध सीरीज हैना मोंटाना की तरह दोहरी जिंदगी जी, लेकिन जीने का तरीका शानदार था। अभिनेत्री मॉडलिंग के साथ-साथ एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रही थी। एमबीबीएस की पढ़ाई ही अपने आप में मुश्किल है, और ऐसे में मिस वर्ल्ड जैसे बड़े सपने के लिए भी तैयारी करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है।

फिल्म पृथ्वीराज से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मानुषी ने साल 2017 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और फिर इसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी अपने नाम किया। अभिनेत्री मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली छठी भारतीय महिला बनी थी।

बिकिनी पहन पानी में आग लगाती दिखीं एक्ट्रेस प्रज्ञा जैसवाल, हॉटनेस देख फैंस को सर्दी में भी आया पसीना

एक्ट्रेस प्रज्ञा जैसवाल इन दिनों अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक की वजह से चर्चा में हैं। एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली प्रज्ञा फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने मालदीव्स वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस उन पर दिल हार बैठे हैं।

प्रज्ञा इन दिनों मालदीव्स में छुट्टियां बिता रही हैं। नीले समंदर, खूबसूरत मौसम और लग्जूरियस लोकेशन के बीच एक्ट्रेस ने अपने शानदार पलों को कैमरे में कैद किया है। उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस लगातार उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे।

तस्वीरों में एक्ट्रेस लाइम ग्रीन कलर की बिकिनी में नजर आ रही हैं। इस लुक में उनका कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस अंदाज साफ झलक रहा है। समुंदर के बीच जहाज पर पोज देती हुईं प्रज्ञा बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

वहीं एक फोटो में वह पानी के बीच नेट पर लेटी दिखाई दे रहीं हैं, जहां समंदर के नजारे और उनका स्टाइल दोनों फैंस को इंप्रेस कर रहा है। जिसपर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं और वो दीवानें हो रहे हैं।

बिकिनी लुक के अलावा प्रज्ञा ने लाइम ग्रीन डीपनेक ड्रेस में भी अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। ब्लैक सनग्लासेस और स्टाइलिश हेयरडू के साथ उनका ये अंदाज और भी अट्रैक्टिव दिख रहा है। इन फोटोज में प्रज्ञा का कॉन्फिडेंस और एलिगेंस दोनों नजर आ रहा है।

एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं। किसी ने उन्हें बेहद खूबसूरत बताया तो किसी ने उनके लुक को किलर कहा। प्रज्ञा के कमेंट सेक्शन में दिल और फायर इमोजी की बाढ़ आ रही है।

तस्वीरों के अलावा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रज्ञा एक कुक के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत कर रही हैं। फैंस को उनका ये क्यूट अंदाज़ भी काफी पसंद आया।

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रज्ञा जैसवाल साउथ फिल्मों में बड़ा नाम हैं। वह अखंडा और डाकू महाराज जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बॉलीवुड में वो आखिरी बार फिल्म खेल खेल में में नजर आईं थीं। उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर फैंस भी खासे एक्साइटेड हैं।

विदेशो में बॉर्डर 2 ने प्री टिकट सेल में काटा गदर, रिलीज से पहले ही वॉर 2 और धुरंधर को दी पटखनी

सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। वहीं इस मच अवेटेड फिल्म की की टिकटें 19 जनवरी, सोमवार से बिकनी शुरू हो रही हैं, हालांकि कुछ जगहों पर कल रात से ही टिकटें बिकनी शुरू हो गई हैं। इन सबके बीच विदेशों में, फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले से हो रही है और शुरुआती नतीजे शानदार हैं। जानत हैं विदेशो में बॉर्डर 2 की अब तक कितनी प्री टिकट सेल हो चुक है?

ऑस्ट्रेलिया में, फिल्म ने वॉर 2 और धुरंधर से लगभग दोगुनी कमाई की है। कनाडा में, सबसे बड़ी सिनेमा चेन, सिनेप्लेक्स ने अभी तक बुकिंग शुरू नहीं की है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चेन, लैंडमार्क सिनेमाज ने बुकिंग शुरू कर दी है, जहां फिल्म के मुख्य स्थानों पर 2-3 शो में लगभग 100 टिकटें बिक चुकी हैं। अमेरिका में भी इसी तरह के नतीजे देखने को मिल रहे हैं, जहां मेजर हिंदी सिनेमाघरों में 1-2 शो में अच्छी बिक्री हो रही है। जर्मनी में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

इस फिल्म का बैकड्रॉप भारत-पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है। ऐसे में उम्मीद है कि ये फिल्म मिडिल ईस्ट में रिलीज़ नहीं होगी।

फिलहाल, इसकी प्री टिकट सेल लिमिटेड लेवल पर हो रही है। आज से और आने वाले दिनों में शो की संख्या बढ़ाई जाएगी और बिक्री में भी उसी रेश्यो के साथ इजाफा होगा। हालांकि, सबसे जरूरी बात ये है कि ये शुरुआती प्री-सेल्स फिल्म के लिए लोगों की ज़बरदस्त दिलचस्पी दिखाती है। यह देखा गया है कि जो फिल्में विदेशों में प्री-सेल्स में अच्छा परफॉर्म करती हैं, वे घरेलू स्तर पर भी वैसा ही प्रदर्शन करती हैं। गदर 2 भारत में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी और विदेशों में भी इसने ठीक-ठाक कमाई की थी। विदेशी बाज़ारों में 'बॉर्डर 2' की शुरुआती प्री-सेल्स 'गदर 2' से कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं, जो एक अच्छा साइन है।

'बॉर्डर 2' इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। वहीं पिंकविला के पीडिक्शन के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन लगभग 40 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है। टीज़र को ज़बरदस्त रिस्पॉन्सम मिला है और इसका म्यूज़िक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में रिलीज़ हुए ट्रेलर को भी पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है। ये सब देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि 'बॉर्डर 2' शानदार शुरुआत कर सकती है। बता दें कि ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित । शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com